● वर्ष-2
● अंक-279
रायपुर, शुक्रवार
14 जुलाई 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

प्रधानमंत्री मोदी पेरिस पहुंचे

भारतीय समुदाय के लोगों से मिले, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच गए। वे सुबह दिल्ली से फ्रांस के लिए रवाना हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी के पेरिस पहुंचने पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया। फ्रांस की पीएम एलिजाबेथ बोर्न ने उनकी अगुवाई की। प्रधानमंत्री मोदी जब अपने होटल प्लाजा एथेनी पहुंचे तो बाहर भारतीय समुदाय के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ्रांस में मुलाकात के बाद भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति ने कहा कि मैं मोदी जी से तीसरी बार मिला हूं, बहुत अच्छा लगा मिलकर। मोदी जी जब-जब फ्रांस आते हैं मैं उनसे मिलता हूं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री यहां आते हैं और हमसे मुलाकात करते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के साथ-साथ यूएई का भी दौरा करेंगे। 13 और 14 को पीएम फ्रांस में रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 14 जुलाई को फ्रांस के बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। फ्रांस के बाद 15 जुलाई को पीएम मोदी यूएई जाएंगे।

फ्रांस के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि हम लोग क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर साथ में काम करेंगे। मैं राष्ट्रपति मैक्रों से मिलने के लिए उत्सुक हूं। फ्रांस की

प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न, सीनेट अध्यक्ष जेरार्ड लार्चर और नेशनल असेंबली अध्यक्ष येल ब्रौन-पिवेट के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे विश्वास है कि यह यात्रा रणनीतिक साझेदारी को नई पहचान देगी।

भारतीय समुदाय से पहले दिन ही करेंगे मुलाकात

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर पीएम मोदी आज फ्रांस के लिए रवाना होंगे। मैक्रों पीएम मोदी के सम्मान में राजकीय भोज के साथ-साथ एक निजी रात्रि भोज की मेजबानी भी करेंगे। पीएम की फ्रांस यात्रा रणनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के रूप में देखी जा रही है। फ्रांस दौरे पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों का जोर चीन पर निर्भरता कम करने के साथ ही बढ़ाने का रह सकता है। विदेश सचिव विनय मोहन यात्रा ने बताया पीएम मोदी छठी बार फ्रांस जा रहे हैं। वह बृहस्पतिवार दोपहर तक फ्रांस पहुचेंगे और शाम को भारतीय समुदाय के साथ भेंट करेंगे।

पीएम मोदी 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर बैस्टिल डे या बास्तील दिवस परेड में शामिल होंगे। इसके बाद फ्रांसीसी पीएम, सीनेट और नेशनल असेंबली के अध्यक्षों के साथ-साथ फ्रांसीसी कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात करेंगे। फ्रांस से लौटते वक्त 15 जुलाई को पीएम मोदी यूएई जाएंगे, जहां वे यूएई के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से चर्चा करेंगे। यह यात्रा ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का मौका देगी। मुख्य अतिथि बनने वाले

दूसरे भारतीय पीएम होंगे मोदी

भारतीय पीएम को अपने राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाना भारत और फ्रांस के गहरे होते रणनीतिक रिश्तों के अहम संकेत है। मोदी दूसरे भारतीय पीएम होंगे, जिन्हें फ्रांस ने मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। 2009 में मनमोहन सिंह को आमंत्रित किया गया था।

कारोबारी संबंध बढ़ाने पर जोर

भारत-फ्रांस के बीच गहरे रणनीतिक संबंध होने के बाद भी दोनों के बीच कारोबारी रिश्ता बहुत उत्साहजनक नहीं है। 2010 से 2021 तक दोनों देशों के द्विपक्षीय कारोबार में करीब 4 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। वैश्विक स्तर पर दोनों देश रणनीतिक हित साझा करते हैं, इस लिहाज से दोनों देशों का जोर अब कारोबारी रिश्तों को बढ़ाने पर है।

परमाणु परीक्षण के वक्त भारत के साथ था फ्रांस

आजादी के बाद यूरोप में फ्रांस लंबे समय तक भारत का सबसे बड़ा साझेदार रहा। 1998 में दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई। इस वर्ष जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए, तो अमेरिका सहित तमाम पश्चिम देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए। हालांकि, फ्रांस न केवल प्रतिबंधों से दूर रहा, बल्कि प्रतिबंधों को हटाने के लिए पुरजोर पैरवी भी करता रहा। इस तरह से बीते तीन दशक में भारत के लिए रूस के बाद फ्रांस सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा।

भारतीय सेना का साथ मिला तो गर्व से फूल उठा फ्रांसीसी सेना का सीना

फ्रांसीसी नेशनल डे पर होने वाली परेड में इस साल भारतीय सेना के जवानों के शामिल होने से फ्रांसीसी सेना गौरवान्वित महसूस कर रही है। यह परेड दुनिया के सबसे खूबसूरत रास्तों में शुमार एवेन्यू शॉन्ज एलिसीज पर होगी। भारतीय सेना के तीनों अंगों के वरिष्ठ अधिकारी परेड की रिहर्सल के लिए पेरिस में मौजूद हैं। फ्रांसीसी सेना का कहना है कि इस बार परेड में भारतीय सेना के का साथ मिलना उनके लिए गर्व की बात है।

बिहार में भाजपा ने जबरदस्त तरीके से नीतीश कुमार और सरकार के खिलाफ हमलावर है। राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति और तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा ने आज मार्च का आयोजन किया था। यह मार्च गांधी मैदान से विधानसभा की ओर जानी थी।

प्रेमसाय टेकाम का इस्तीफा, मरकाम बनेंगे मंत्री

रायपुर। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने शालेय शिक्षा मंत्री डा. प्रेमसाय सिंह टेकाम का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कल विधायक दल की बैठक के बाद टेकाम ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर राज्यपाल को मंजूरी के लिए अनुशंसा पत्र के साथ भेज दिया था। राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार लिया है।

आज उनकी जगह पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम को मंत्री बनाया जा रहा है। राजभवन

में शुक्रवार 11 बजे एक सादे समारोह में मोहन मरकाम मंत्री पद की शपथ लेंगे। संभवतः प्रेमसाय टेकाम का विभाग ही मरकाम को दिए जा सकते हैं। वही चुनाव के पहले इस तरह के फेरबदल को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि संगठन में लोगों को अलग-अलग जिम्मेदारी मिलती रहती है। मोहन मरकाम का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। सभी प्रदेशों में बदलाव हो रहे हैं और रायपुर महाअधिवेशन में पारित हुआ था कि 50 प्रश जो सीटे हैं, वह 50 साल के कम उम्र वालों को मिलनी चाहिए। हमारे यहां शुरुआत हो रही है दीपक बैज अभी 42 के हैं। टेकाम का पार्टी में कहीं और उपयोग किया जायेगा वे पार्टी के समर्पित व निष्ठावान सम्मानित सदस्य हैं।

इन दिनों ✍ बरुण सखाजी

प्रदेश में तस्वीर कांग्रेस की

चुनावी साल में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में कई बदलाव किए हैं। जनवरी-फरवरी तक चल रहे इकतरफावाद पर लगाम लगाते हुए प्रदेश प्रभारी बदले, अप्रासंगिक हो रहे कद्दावार मंत्री को डिप्टी बनाकर फिर प्रासंगिक बनाया, अब दो बड़े बदलाव प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री के रूप में बैक टु बैक कर दिए गए। कांग्रेस जानती सरकार भले ही आंखें दिखाकर चला ली लेकिन चुनाव चुनाव की तरह ही लड़ने होंगे। परसेप्शन और जमीन का जब तक संतुलन नहीं होगा तब तक चुनाव जीते नहीं जा सकते। चेहरों पर चुनाव होने का फॉर्मूला तभी चलता है जब मैदान में भी काम दिखे। सिर्फ जन संपर्क कंपनियों के गढ़े चेहरों से काम नहीं चल सकता। पुरानी सरकार में डॉ. रमन सिंह के रूप में भाजपा के पास एक आजमाया हुआ चेहरा था, लेकिन 2017 से ही ऐसा लग रहा था कि अबकी बार सारा माहौल सिर्फ जन संपर्क कंपनियों का बनाया हुआ है, मैदान में गिल्लियां उड़ रही हैं। फिलवक्त बघेल सरकार के मामले में हालात भले उतने खराब नहीं, लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं हैं। राजनीति में चुनाव ही आपकी दौड़ को नापने का जरिया हैं। ऐसे में 2023 में जिस तरह से भाजपा ने फोकस किया है उससे लगता है कांग्रेस को बेफिक्र नहीं होना चाहिए। हाल के बदलाव बताते हैं कांग्रेस बेफिक्र नहीं है। बस्तर में भाजपा ने समाज में घुले धर्मांतरण को जिस तरह से पकड़ा है वह उसे वहां बढ़त देता दिख रहा है। मैं यहां किन्हीं सर्वे एजेंसियों की फर्जी बातों पर विश्वास करने को नहीं कह रहा, लेकिन बहुत बारीकी से जन-मन को समझा जाए तो कांग्रेस इकतरफा जीत जैसी स्थिति में नहीं है। बस्तर को संभालने के लिए कांग्रेस ने 2 मंत्री उतार दिए हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष भी मैदान में बनाए रखा है। कयासों पर जरा भी विश्वास करें तो एक और मंत्री वहां से बनाया जा सकता है। यानि अरविंद नेताम के सर्व आदिवासी समाज वाले प्रयोग और भाजपा के धर्मांतरण वाले तड़के को नकारते हुए भी कमतर नहीं आंका जा रहा। यही असल में चतुर राजनीतिक दल की पहचान है। सरगुजा में अधिकतम पर बैठी कांग्रेस मानती है अधिकतम को ही फिर से हासिल करना संभव नहीं है, लेकिन उपमुख्यमंत्री के रूपमें सिंहदेव की ताजपोशी सरगुजा में यहां के अधितकतम को बहुत कम नहीं होने देगी। सरगुजा से अब दो ही मंत्री हैं। इनमें एक उपमुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस मानती है 14 सीटों में दो मंत्री पर्याप्त हैं। पुरानी सरकारों में भी ऐसा ही ट्रेंड रहा है। छत्तीसगढ़ में 80 लाख आदिवासी आबादी में 54 लाख मतदाता हैं। इनमें से 2018 में कांग्रेस के खाते में 25 आदिवासी आरक्षित सीटें और लगभग 33 लाख वोट आए थे। भाजपा ने करीब 17 लाख आदिवासी वोट हासिल किए थे, जबकि जोगी की पार्टी ने भी लगभग 4 लाख वोट हासिल किए थे। कांग्रेस से सदन में 2018 में 28 आदिवासी विधायक थे, जो उपचुनाव के बाद बढ़कर 29 हो गए। भाजपा के घटकर 2 रह गए। इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस आदिवासी वोटर्स को किसी हाल में खोना नहीं चाहती, क्योंकि 2019 में सारे लोग भाजपा में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन आदिवासी वोटर्स में यह स्विच कम था। कांग्रेस ने इन्हीं वोटों के बूते पर दीपक बैज के रूप में एक सीट हासिल की है। हारती हुई कोरबा लोकसभा सीट को आदिवासी बाहुल्य पाली विधानसभा के इकतरफा टर्नआउट ने कांग्रेस की झोली में डाला है। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग में छत्तीसगढ़ की 64 सीटें हैं। इन्हें लेकर भी कांग्रेस को रणनीति बनाना होगी। ओबीसी चेहरे के रूप में बघेल ताकतवर हैं। मंत्रियों में ताम्रध्वज, उमेश पटेल ओबीसी, रविंद्र चौबे, टीएस सिंहदेव, मो. अकबर सामान्य, शिव डहरिया, रुद्र गुरु एससी, कवासी लखमा, अनिला भेंडिया समेत 3 एसटी मंत्री हैं। निष्कर्ष में देखें तो कांग्रेस सरगुजा, बस्तर के समीकरणों को साधते हुए दिख रही है। बिलासपुर में कमजोर है, रायपुर में फिफ्टी-फिफ्टी दिख रही है, दुर्ग थोड़ा फेवरेबल है। इस तरह से कांग्रेस को अभी और बदलाव की जरूरत है। इनमें समग्रता में चुनाव लड़ना सबसे बड़ी नीति सिद्ध हो सकती है।

प्रमुख समाचार

1981 में नरेंद्र मोदी एमए की पढ़ाई कर रहे थः शीला भट्ट

नईदिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर कांग्रेस पार्टी व अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं।

लेकिन जानी मानी पत्रकार शीला भट्ट ने पीएम मोदी की शिक्षा को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 1981 में नरेंद्र मोदी एमए की पढ़ाई कर रहे थे। समाचार एजेंसी एएनआई के पॉडकास्ट में पत्रकार शीला भट्ट ने कहा कि जब वो एमए कर रहे थे। उनके मेंटर प्रवीण सेठ जो मेरे भी मेंटर थे। मोदी वहां रोज आते थे। 1981 में मोदी बहुत ही पढ़ाई लिखाई करते थे और मुझे बहुत कुछ याद है। वो एमए की पढ़ाई कर रहे थे और मैं उनकी एक क्लासमेट को भी जानती हूं। मैंने कुछ दिन पहले फोन करके भी पूछा था जब अरविंद केजरीवाल ट्विटर पर और इधर उधर बहुत लिख रहे थे। बीजेपी के मीडिया सेल के हेड अमित मालवीय ने समाचार एजेंसी एएनआई का क्लिप साझा करते हुए कहा कि वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट प्रधानमंत्री के छात्र दिनों को याद करते हुए कहा कि मैं मोदी से 1981 में मिली थी जब वह एमए कर रहे थे।

महाराष्ट्र में कांग्रेस करेगी विपक्ष का नेतृत्वः पृथ्वीराज चव्हाण

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी हलचल जारी है। जबसे अजित पवार ने महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है, तब से सत्ता पक्ष और विपक्ष में

दोनों ही तरफ राजनीतिक सुगबुगाहट में तेजी देखी गई है। सत्ता पक्ष में जहां एक ओर आम सहमति नहीं बना पा रहा है तभी तो मंत्रालयों के बंटवारे और कैबिनेट विस्तार का मामला अटका पड़ा है। तो दूसरी ओर शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस मिलकर एकजुटता तो दिखा रहे हैं, लेकिन नेतृत्व को लेकर सभी के अपने-अपने दावे हैं। इन सबके बीच कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर दावा कर दिया गया है कि महाराष्ट्र में विपक्ष का नेतृत्व वही करने जा रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण की ओर से कहा गया है। महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए कांग्रेस का यह बयान झटका इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जहां महा विकास आघाडी का नेतृत्व ठाकरे ने किया था तो वहीं शरद पवार लगातार कांग्रेस से ज्यादा ताकत महाराष्ट्र में रखते रहे हैं। एनसीपी में फूट के बाद कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया

अन्नामलाई की दक्षिण भारत में 5 महीने की लंबी पदयात्रा

नईदिल्ली। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई 28 जुलाई से शुरू होने वाली अपनी पांच महीने की पैदल यात्रा की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। एन मन, एन मक्कल जिसका अर्थ

है मेरी मिट्टी, मेरे लोग। इसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और पार्टी को उम्मीद है कि कार्यक्रम के पहले दिन 1.5 लाख से अधिक लोग भाग लेंगे। भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष नारायणन तिरुपति ने कहा कि पदयात्रा सभी निर्वाचन क्षेत्रों और जिलों को कवर करेगी। इसका उद्देश्य तमिल लोगों को केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों के बारे में बताना है। तिरुपति ने कहा कि हम डीएमके शासन के कुशासन का भी पर्दाफाश करेंगे। यात्रा के प्रत्येक स्थान पर हमारे 100 से अधिक स्वयंसेवक होंगे। भाजपा ने रैली के शुरुआती बिंदु के रूप में रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम को चुनने का फैसला किया है। इसको लेकर तिरुपति ने कहा कि रामेश्वरम एक पवित्र स्थान है और यह तमिलनाडु के सिरे पर भी है। हम कन्याकुमारी या रामेश्वरम में से किसी एक को चुनना चाहते थे।

असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक जल्द

नईदिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि सरकार राज्य में बहुविवाह पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है और आगामी विधानसभा सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा। बहुविवाह, एक ही समय में एक से अधिक पत्नी या पति रखने की प्रथा है। भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के बारे में चल रही चर्चा में एक आवर्ती विषय बन गई है। असम सरकार ने इस कदम को लागू करने के लिए कानूनी पहलुओं का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसे राज्य द्वारा समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास के रूप में देखा गया था। रिपोर्ट लंबित है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि हम आगामी विधानसभा सत्र में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पेश करने की योजना बना रहे हैं। अगर किसी कारण से हम ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं तो हम जनवरी विधानसभा सत्र में विधेयक पेश करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि असम में हम बहुविवाह पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ष्टष्ट आता है, तो हमें कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका ष्टष्ट में विलय हो जाएगा।

यूरोपीय संसद में मणिपुर हिंसा पर बहस, मोदी सरकार का जवाब

नईदिल्ली। भारत ने मणिपुर और राज्य में हुई हिंसा पर तत्काल बहस कराने के यूरोपीय संघ के आह्वान को खारिज कर दिया है। भारत सरकार ने बुधवार को कहा कि यह मामला पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला

है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि हमने यूरोपीय संघ के सांसदों तक पहुंचने के प्रयास किए। यह मामला पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। 11 जुलाई को यूरोपीय संघ ने मानवाधिकारों, लोकतंत्र और कानून के शासन के उल्लंघन के मामलों पर बहस के एजेंडे में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव जारी किया। इसने इस आधार पर बहस आयोजित करने का बचाव किया कि यूरोपीय संघ और भारत दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं जो मानवाधिकारों की रक्षा और प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हैं। जबकि भारत के मणिपुर राज्य में मुख्य रूप से हिंदू मैतेई समुदाय और ईसाई कुकी जनजाति के बीच जातीय और धार्मिक आधार पर हिंसा भड़क उठी है, जिससे हिंसा का एक चक्र शुरू हो गया है, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए, 40,000 से अधिक विस्थापित हुए और संपत्ति और पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया गया। इसमें कहा गया है।

ऑनलाइन गेमिंग पर सख्ती बनाम कर लगाने की पद्धति और सांविधानिकता की कसौटी

अजय बग्गा

मंगलवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक हुई, जिसे कर व्यवस्था में मील का पत्थर कहा जा सकता है। दरअसल काफी विमर्श के बाद जीएसटी को लागू किया जा सका था। इससे पहले परिषद की 49 बैठकें हुईं, जिनमें करीब 1,500 फैसले किए गए, जो सहकारी संघवाद की भावना को प्रदर्शित करते हैं। इसमें कर आकलन के अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई। वित्तमंत्री ने बताया कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण राज्यों की राजधानियों में स्थापित किए जाएंगे, जहां उच्च न्यायालय की बेंच है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण इस वित्तीय वर्ष से काम करने लगेगा।

इस बैठक से पहले सरकार ने सात जुलाई को एक अधिसूचना के जरिये जीएसटीएन को पीएमएलए के दायरे में ला दिया है, जो जीएसटीएन, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य जांच एजेंसियों के बीच जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में स्वाभाविक रूप से इस पर सवाल उठे। आम आदमी पार्टी शासित पंजाब और दिल्ली के वित्त मंत्रियों ने आशंका जताई कि इससे %कर आतंकवाद% को बढ़ावा मिल सकता है और करोड़ों जीएसटी धारकों को ईडी द्वारा प्रताड़ित किया जा सकता है। लेकिन केंद्रीय वित्तमंत्री ने राज्यों को बताया कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) के दायित्वों को पूरा करने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईडी मामलों को जीएसटीएन को भेज सकता है, जबकि जीएसटीएन डाटा ईडी को नहीं भेजा जाएगा। वित्तीय खुफिया ईकाई (एफआईयू) के निदेशक को जब लगेगा कि कर चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो वह अधिकारियों को जानकारी प्रदान करेंगे।

जीएसटी परिषद ने चार वस्तुओं पर कर कटौती को मंजूरी प्रदान की। कैंसर एवं दुर्लभ

बीमारियों के उपचार में काम आने वाली दवाओं और पूरक या विशेष चिकित्सा प्रयोजन के खाद्य के आयात को जीएसटी से मुक्त रखने का निर्णय सबसे स्वागत योग्य फैसला है। इससे दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों को राहत मिलेगी और उनके इलाज की लागत में कमी आएगी। उपग्रह प्रक्षेपण क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि इसरो, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) द्वारा दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर जीएसटी छूट को निजी क्षेत्र के संगठनों को भी उपलब्ध करवाया जा सकता है, ताकि ऐसे निजी खिलाड़ियों को भारत में इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।ऑटोमोबाइल के मामले में अतिरिक्त उपकर लगाने के लिए एमयूवी और एसयूवी की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। कुछ राज्यों के प्रतिनिधियों के अनुरोध पर सेडान को एसयूवी के निर्धारित आकार पर 22 फीसदी तक उपकर की वृद्धि से छूट दी गई है। कोई भी उपयोगिता वाहन, जिसकी लंबाई चार मीटर से अधिक है, जिसकी इंजन क्षमता 1,500 सीसी से अधिक है और 170 मिमी से अधिक ग्राउंड क्लीयरेंस (बिना लदाई के) है, उस पर 28 प्रतिशत जीएसटी के अलावा 22 प्रतिशत मुआवजा उपकर लगेगा। हालांकि, यह सेडान पर लागू नहीं होगा।

सिनेमा हॉल में परोसे जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों पर अब 18 फीसदी के बजाय पांच फीसदी जीएसटी लगेगा, जिसका सिनेमा मालिक कंपनियों ने स्वागत किया है। सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली घोषणा ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और घुड़दौड़ के लिए पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने की थी। नतीजतन बुधवार सुबह सबसे बड़ी कैसीनो संचालन कंपनी के शेयर की कीमत में भारी गिरावट आई।

वित्तमंत्री ने बताया कि %जीएसटी काउंसिल का इरादा ऑनलाइन गेमिंग उद्योग या राज्यों को नुकसान पहुंचाना नहीं है। काउंसिल ने इस पर गंभीरता से विचार करके फैसला लिया है, जो दो-तीन वर्षों से लंबित था। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने की प्रभावी तारीख जीएसटी कानून में संशोधन के बाद लागू होगी।ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां लंबे समय से खुद को सट्टेबाजी और जुआ व्यवसायों से अलग माने जाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, जिनकी समाज में नकारात्मक छवि है और जिन पर कठिन कर प्रावधान लागू हैं। इस फैसले से भारत में फल-फूल रहे ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को 1.6 अरब डॉलर का नुकसान होता दिख रहा है। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म इंडिया प्लेज के मुख्य परिचालन अधिकारी आदित्य शाह ने कहा, %28 फीसदी कर दर लगाने से गेमिंग उद्योग के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा होंगी। यह उच्च कर बोझ कंपनियों के नकदी प्रवाह को प्रभावित करेगा, जिससे नवाचार, अनुसंधान और व्यापार विस्तार में निवेश करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाएगी।वित्तमंत्री ने दिसंबर, 2022 में संसद को बताया था, भारत के साथ-साथ विदेशों में भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने अप्रैल 2019 से नवंबर, 2022 तक 229 अरब रुपये के जीएसटी की चोरी की। गेमिंग कंपनियों ने कुछ राज्य सरकारों के प्रतिबंधों को अदालतों में चुनौतियां दी हैं। वैश्विक उदाहरण देखें, तो अमेरिका कैसिनो और गेमिंग पर 50 फीसदी से ज्यादा कर लगाता है, फ्रांस जैसे कई यूरोपीय देशों में कर की दर 80 फीसदी तक है, जबकि कैसिनो और जुआ गतिविधियों के प्रमुख केंद्र मकाउ में कर की दर 30 फीसदी है। केन्या ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग की लत के प्रसार को रोकने के लिए इस पर कर दर को 15 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी कर दिया है।

बिरेतरा में विधायक ने किए लाखों के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण

धमतरी। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधायक रंजना साहू के अथक प्रयास से अनगिनत उपलब्धियों से भरा अनेक निर्माण कार्यों की स्वीकृति क्षेत्र की जनता की मांगों को स्वीकार करते हुए बहुप्रतीक्षित मांगों की स्वीकृति दिला रही है, जिससे धमतरी में विकास की गंगा बह रही है।

इसी क्रम में विधायक निज ग्राम बिरेतरा में विधायक की अनुशंसा से स्वीकृत 6 बिस्तर अस्पताल निर्माण कार्य का लोकार्पण, हाई स्कूल में अति कक्ष निर्माण का लोकार्पण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भवन निर्माण का लोकार्पण, प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण का लोकार्पण, समुदायिक भवन शेड एवं अहाता निर्माण का भूमिपूजन, सर्व समाज अष्ट जाति में आहता निर्माण का भूमिपूजन समस्त ग्रामीण वरिष्ठजन, प्रबुद्धजन, स्थानीय विभिन्न जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के सदस्यगण एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में विधिविधान से महाराज जी के आशीर्वचन मंत्रोच्चार के साथ विधायक रंजना डीपेंद्र साहू के कर कमलों से संपन्न हुआ। आए हुए समस्त अतिथियों का पुष्पा कुछ भेंट करते हुए तिलक लगाकर स्वागत अभिनंदन ग्राम पंचायत एवं ग्राम वासियों के द्वारा किया गया अतिथि उद्बोधन में विधायक रंजना साहू ने कहा कि गांव के विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं, बस आपका स्नेह और आशीर्वाद चाहिए, निर्माण कार्य सतत प्रक्रिया है और जनहित के लिए कार्य करना जनप्रतिनिधि का दायित्व है, जितने भी निर्माण कार्य संपन्न हो रहे हैं उनको सहजते हुए रखरखाव एवं साज-सज्जा पर ध्यान केंद्रित करना समस्त ग्रामीणों का दायित्व है।

कार्यक्रम कि विशिष्ट अतिथि पुर्व महापौर अर्चना चौबे ने कहा कि मांग के अनुरूप विधायक ने क्षेत्र विकास के लिए कोई कसर विधायक ने नहीं छोड़ी। पुर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बालाराम साहू जी ने कहा कि धमतरी विधानसभा के विकास में विधायक रंजना साहू ने नए आयाम स्थापित किए हैं, उनका विकास के प्रति योगदान सराहनीय है।लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न होने पर समस्त ग्रामवासियों को बधाई देते हुए जिला पंचायत सदस्य दमयंती केशव साहू, जनपद सदस्य जागेश्वरी राकेश साहू, भाजपा आमदी मंडल अध्यक्ष मुरारी यदु, आमदी मंडल महामंत्री अमन राव, जिला कोषाध्यक्ष चेतन हिंदूजा, पूर्व जनपद सदस्य भगत यादव, पूर्व जनपद सदस्य डीपेंद्र साहू, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष अवनेंद्र साहू ने समस्त ग्रामीणों को निर्माण कार्य की बधाई एवं शुभकामनाएं दिए और निरन्तर देश हित, समाज हित, गांव हित के लिए कार्य करने की बात कहा गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चिरौंजी साहू, धौराभाठा सरपंच किरण मुरली सिन्हा, सिराज सिंह, बिहारी राम साहू, नूतन राम साहू, रामखिलावन, चितेरी राम साहू, नरेंद्र साहू, उत्तम साहू, पारथ राम साहू, पीलू राम साहू, कैसु राम साहू, अलख राम सेन, टीका राम साहू, बलदेव राम साहू, अंजोर ध्रुव, गुलाब राम साहू, गोपी राम निर्मलकर, गुहन यादव, तेज राम निर्मलकर, लोचन राम तारक, देवेंद्र बया, ओमप्रकाश विश्वकर्मा, सिया राम पटेल, झुमुक राम साहू, परसराम साहू, महेतरु राम साहू, भरोसा राम साहू, सुखलाल साव, सेवा राम साहू, मन्सा राम साहू, ढालूराम साहू, बसंत राम साहू, भीखम साहू, सरपंच उषा भीखम साहू, उपसरपंच विनेश्वर साहू, सहित समस्त पंचायत सदस्य गण एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र समिति की सदस्य बनाई गईं रंजना साहू

धमतरी। प्रदेश भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर घोषणा पत्र समिति का गठन किया है। इस समिति में 31 पदाधिकारियों को रखा गया है। सांसद विजय बघेल को समिति का संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, विधायक शिवरतन शर्मा को सहसंयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। समिति में कुल कुल 31 लोग है जिसमें धमतरी जिले से एकमात्र नाम विधायक रंजना डीपेन्द्र साहू का है। ज्ञात हो कि उक्त समिति द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए घोषणा पत्र की बिन्दु तैयार करेगी जल्द ही समिति की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि समिति के सदस्य दौरा भी कर सकते है। किसी भी चुनाव में घोषणा पत्र ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में धमतरी जिले से विधायक रंजना साहू को टीम में शामिल कर एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उल्लेखनीय है कि विधायक रंजना साहू धमतरी विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय है। भाजपा को मजबूत करने लगातार जुटी रहती है। उनकी सक्रियता व नेतृत्व क्षमता को देते हुए पार्टी द्वारा उन्हें पूर्व में प्रदेश प्रवक्ता भी बनाये गये है। हाल ही में विधानसभा में उत्कृष्ट विधायक भी चुनी गई है। भाजपा से प्रदेश भर में एक मात्र महिला विधायक है। जनहित के मुद्दों को लेकर हमेशा मुखर रहती है। विधानसभा में भी वरिष्ठ मंत्रियों को घेरने में सफल रहती है। ऐसे में घोषणा पत्र समिति में उन्हें शामिल कर प्रदेश भाजपा ने उनका कद और बढ़ाया है। विधायक रंजना साहू को समिति में शामिल किये जाने से जिले के भाजपाईयों में हर्ष है। व भाजपाईयों उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दे रहे है।

फोरलेन प्रभावितों को नहीं मिला मुआवजा 16 को विधायक कंवर करेंगे चक्काजाम

कोरबा। विधायक व पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने कहा कि फोरलेन व भारतमाला सड़क के प्रभावितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। निजी जमीन को शासकीय जमीन बता कर टालमटोल की नीति अख्तियार की जा रही है। क्षेत्रवासियों की नौ सूत्रीय मांग लेकर 16 जुलाई को तहसील मुख्यालय बरपाली में सांकेतिक चक्काजाम किया जाएगा।

भाजपा कार्यालय दीनदयाल कुंज में पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधायक कंवर ने कहा कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत के विभिन्न समस्याएं बरकरार है। समय-समय पर ग्रामीणों द्वारा अवगत कराने के बाद भी समस्याओं का निराकरण नहीं हो सका है। इसलिए आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दोपहर दो से शाम पांच बजे तक चक्काजाम किया जाएगा। इसके बाद भी समस्या का निदान नहीं किया गया, तो अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों की मांग रखते हुए विधायक ने कहा कि कोरबा-चांपा फोर लेन सड़क निर्माण के प्रभावितों की निजी जमीन को शासकीय भूमि बताकर उचित मुआवजा नही दिया जा रहा है। इसी तरह उरगा. पत्थलगांव भारत माला प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित किसानों को मुआवजा की विसंगति को दूर नहीं की गई है।

उरगा स्थित खनिज विभाग जांच नाका को कीचड़ एवं धूल प्रदुषण से मुक्त करने, वर्ष 2021 में धान खरीदी के चार किस्त की राशि का अविलंब प्रदाय करने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए नि:शुल्क अनाज जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक का प्रदाय करने, लैको के भू-विस्थापितों को नौकरी प्रदान करने, किसानों की मांग अनुसार खाद. यूरिया डीएपी प्रदाय करने व केचुआ खाद के नाम पर गुणवत्ताहीन खाद की अनिवार्यता हटानेए जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत एवं अतिरिक्त प्रस्तावित कार्यो को समय पर पूर्ण करने, विद्युत विभाग करतला कनिष्ठ यंत्री भूपेन्द्र राठौर को रामपुर विधानसभा से बाहर पदस्थ करने, करतला व भैंसमा में नए कनिष्ठ यंत्री पदस्थ करने तथा बरपाली सरगबुंदिया, रेल्वे कोयला साइडिंग तत्काल बंद करने की मांग रखी गई है। समस्या का निदान नहीं किया जाता है, तो आगे भी आंदोलन किया जाएगा। सांकेतिक चक्काजाम करते हुए प्रशासन को एक माह का अल्टीमेटम दिया जाएगा। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष आकाश सक्सेना, बरपाली मंडल के अध्यक्ष प्रदीप पटेल, करतला मंडल अध्यक्ष नटवर शर्मा, उरगा मंडल अध्यक्ष कुल सिंह कंवर, कुदमुरा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी श्रीवास व गढ़उपरोड़ा मंडल अध्यक्ष धनसिंह कंवर भी उपस्थित रहे।

रोजगार सहायकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर निकाली रैली

कबीरधाम। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के ग्राम रोजगार सहायक अब अपनी मांग को लेकर लामबंद हो गए है। इन सहायकों ने बुधवार से हड़ताल शुरू कर दी है। इनकी दो सूत्रीय मांग है, जिसमें ग्रेड -पे निर्धारण करते हुए नियमितिकरण किया जाए और नियमितिकरण होने तक ग्राम रोजगार सहायकों का सिविल सेवा आचरण पंचायती राज अधिनियम 1966 पंचायत कर्मी नियमावली को लागू की जाए। अब अपनी मांगों को लेकर रोजगार सहायकों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

पूरे जिले में करीब 450 से अधिक ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायक तैनात है। इनके हड़ताल में चले जाने से पंचायत के सभी प्रकार के कामों पर असर होना शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ के जिला अध्यक्ष राजाराम वर्मा, उपाध्यक्ष रामदास साहू, सचिव गोपाल चन्द्रवंशी ने बताया कि वे मांगों को करीब वर्ष से समय-समय पर शासन के समक्ष रखते आ रहे है। आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की हमारे मांग को लेकर उचित निर्णय नहीं लिया गया है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में पूरे प्रदेश के रोजगार सहायकों ने हड़ताल की थी। इसके बाद शासन की ओर मांग पूरी किए जाने का आश्वासन जरूर मिला। करीब 66 दिन हड़ताल बाद 9540 रुपए देने की घोषणा की गई। लेकिन, वर्तमान में यह मानदेय नहीं मिल रहा है। रोजगार सहायकों ने कहा कि देश के अन्य राज्य मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान की तरह हमारी मांगों को पूरी किया जाए।

नारायणपुर-ओरछा मार्ग में भूलभुलैया ढूंढनी पड़ेगी 55 किमी लंबी सड़क

नारायणपुर। नारायणपुर ओरछा सड़क मार्ग की बदहाली से लोग ना सिर्फ परेशान हो रहे हैं बल्कि इस सड़क की वजह से कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। सड़क में बने गड्ढों से टू व्हीलर और दूसरी गाड़ियां हादसों का शिकार हो रही हैं। हालत ये है कि किसी गर्भवती या गंभीर मरीज को एंबुलेंस में इस रोड से ले जाने में कई घंटों का समय लग जाता है।

नारायणपुर से छोटेडोंगर तक सालभर पहले सड़क बनाई गई। लेकिन 55 किलोमीटर तक सड़क की हालत काफी खराब है। बारिश के कारण पूरी सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई है। पूरी सड़क में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। जिससे यहां से गुजरने वाले लोग हर रोज काफी परेशान हो रहे हैं।

यहां के स्थानीय ग्रामीण और इस सड़क से गुजरने वाले लोग बताते हैं कि सड़क जब बनी थी तब ठीक थी। सड़क बनने के कुछ दिनों बाद ही आमदाई लोह माइंस से वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई और सालभर के अंदर ही सड़क गड्ढे में बदल गई। यानी सड़क निर्माण लोह माइंस के लिए ही कराया गया था।

लगातार भारी गाड़ियों की आवाजाही से रोड पूरी तरह खराब हो चुकी है। आम दिनों में भारी वाहनों के चलते लोग धूल से परेशान रहते हैं। वहीं बारिश के दिनों में पूरी सड़क में गड्ढे होने के कारण पानी भर जाने से आने जाने वाले लोगों को गड्ढे नजर नहीं आते और वे हादसे का शिकार हो जाते हैं। ग्रामीणों ने कई बार आंदोलन कर भारी वाहनों के इस रोड से ना गुजराने की मांग भी की लेकिन मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई।

ग्रामीणों का कहना है कि माइंस खुलने से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ बल्कि ज्यादा परेशानी हो गई। पूरी सड़क खराब हो गई। एंबुलेंस को पहुंचने में भी काफी वक्त लगता है। इधर अधिकारी सड़क खराब होने का पूरा ठीकरा ठेकेदार पर फोड़ते हुए काम नहीं होने पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं।

नारायणपुर से छोटेडोंगर तक सड़क बनने के बाद यहां के ग्रामीण काफी खुश हुए। लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी खुशी को ग्रहण लग गया। आमदाई लोह माइंस तक हर रोज भारी गाड़ियों की आवाजाही होने लगी। धूल का गुबार लग गया। बारिश के दिनों में हादसे बढ़ गए। ग्रामीण अब बड़ी गाड़ियों की आवाजाही बंद करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस मांग पर कितनी सुनवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

एस्मा लगाए जाने के बाद प्रशासन सख्त

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा लगा दिया है। इसके बाद जगदलपुर जिला प्रशासन ने भी सख्त रुख अपना लिया है। प्रशासन की ओर से हड़ताल कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों को तत्काल काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंध समस्त कार्यों और स्वस्थ्य सुविधाओं की अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी तथा एम्बुलेंस सेवाओं में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी द्वारा कार्य करने से इंकार किए जाने की बात सामने आई थी। जिसके बाद आदेश के पालन में हड़ताल वापस लेने के निर्देश दिए गए।

अवैध शराब पकड़ी तो आबकारी विभाग की टीम से भिड़े ग्रामीण

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बुधवार देर रात अवैध शराब पकड़े जाने के बाद जमकर हंगामा हो गया। कार्रवाई करने पहुंची आबकारी विभाग की टीम से ग्रामीण भिड़ गए। टीम को ग्रामीणों ने घेर लिया और धक्का-मुक्की शुरू हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और स्थिति को संभाला। विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि जब्ती बनाने के दौरान ग्रामीण एकत्र हो गए और विरोध करने लगे। हालांकि अभी तक इस संबंध में आबकारी विभाग की ओर से मामला दर्ज नहीं कराया गया है। मामला उरगा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, ग्राम फरसवानी में बुधवार रात आबकारी विभाग की टीम कच्ची शराब की अवैध बिक्री की सूचना पर पहुंची थी। टीम ने कुछ ग्रामीणों के घर में छापा मारकर शराब जब्त भी कर ली। तभी ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंच गई और टीम को घेर लिया। कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों ने आपत्ती जताई और विरोध शुरू कर दिया। दोनों पक्षों में बहस और धक्का-मुक्की होने लगी। इस पर टीम ने पुलिस को सूचना दी।

नक्सल मोर्चे पर जाने के लिए डॉग्स हो रहे तैयार

दुर्ग। नक्सल इलाकों में बारुदी सुरंगें खोजनी हो, ट्रेनों या बस अड्डों में तस्करों को दबोचना हो या फिर किसी जघन्य अपराध वाली जगह में मुजरिम का सुराग ढूंढना हर जगह खोजी कुत्तों की भूमिका सबसे पहले होती है। लेकिन इन डॉग्स में ऐसी क्या खासियत होती है कि पुलिस हो फिर चाहे सेना हर कोई इन पर आंख बंद कर भरोसा करता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे ऐसे ही ट्रेनिंग सेंटर जहां ऐसे डॉग्स को खतरों से मुकाबला करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। छत्तीसगढ़ में प्रदेश का एक मात्र डॉग ट्रेनिंग सेंटर भिलाई के सातवीं बटालियन में है। जहां डॉग्स को ट्रेनिंग देकर उन्हें प्रदेश के दूसरे जिलों में भेजा जाता है। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की सातवीं बटालियन में इन दिनों खासतौर के डॉग स्क्वाड को ट्रेनिंग दी जा रही है। मौजूदा समय में इस ट्रेनिंग कैंप में बेल्जियम शेफर्ड नस्ल के 9 डॉग्स हैं। ये सभी डॉग्स एक ही मां की संतान हैं। बेल्जियम शेफर्ड प्रजाति के ये डॉग्स अभी 6 माह के हैं। जनवरी अंत तक इनकी ट्रेनिंग पूरी होगी।डॉग्स को तीन अलग-अलग केटेगरी में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

भिलाई नगर निगम ने टैक्स पेयर्स को जारी किया अंतिम नोटिस

दुर्ग। भिलाई नगर निगम को टैक्स जमा करने के लिए दिये गये चेक बाउंस होने पर लोगों को नोटिस जारी किया गया था। भिलाई नगर निगम ने ऐसे करदाताओं को नोटिस जारी कर राशि जमा करने कहा गया था। अब निगम ने उन्हें फिर 3 दिन की मोहलत दी है। समय सीमा में पैसे जमा नहीं करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाएगा। भिलाई नगर निगम को 49 करदाताओं ने टैक्स जमा करने के लिए चेक दिया था। लेकिन खाते में पर्याप्त राशि नहीं थीं, तो चेक बाउंस हो गया। जिससे निगम के खाते में राशि जमा नहीं हो सकी। ऐसे करदाताओं को भिलाई नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किया गया था। इनमें से 14 करदाताओं ने टैक्स की राशि जमा कर दी हैं। जबकि 35 लोगों ने राशि जमा नहीं की थीं। उन्हें 3 दिन की मोहलत दी गई है। पैसे जमा नहीं करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ निगम द्वारा एफआईआर दर्ज कराया जाएगा।

सर्व आदिवासी समाज ने यूसीसी का किया विरोध

नगरी। सर्व आदिवासी समाज ने यूसीसी के विरोध में अनुविभागीय कार्यलय नगरी में अनुविभागीय अधिकारी गीता रायस्त को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि समान नागरिक संहिता में सभी धर्मों के लिए एक कानून की व्यवस्था होगी. हर पंथ का पर्सनल लॉ है, जिसमें शादी, तलाक और संपत्तियों के लिए अपने-अपने कानून हैं। यूसीसी के लागू होने से सभी धर्मों में रहने वालों लोगों के मामले सिविल नियमों से ही निपटाए जाएंगे। कुछ दिन पूर्व पिछड़ा वर्ग समाज के द्वारा भी विरोध दर्ज कराया जा चुका है क्षेत्र के समस्त मूलनिवासी समाज इसके विरोध में हैं। इसी कड़ी में सर्व आदिवासी समाज नगरी द्वारा भी इस काले कानून का विरोध किया गया। समाज ने कहा आदिवासियों के पास कोई संहिताबद्ध कानून नहीं है। आदिवासी समुदाय जन्म, तलाक, विभाजन, उत्तराधिकार, विरासत, भूमि और संपत्ति के मामलों में अपने पारंपरिक कानूनों द्वारा शासित होता है और यही इसकी पहचान है, जो बाकी जातियों से अलग है।

दो कमरों में चल रहीं पांच कक्षाएं, एक टीचर और 96 छात्र

■ अब तक 15 ने मांगी अपनी टीसी

बीजापुर। छत्तीसगढ़ में 26 जून को नए शिक्षा सत्र का आगाज हो गया हैं। जिले की अलग-अलग जगहों पर प्रशासन लगातार शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन कर रहा है। बीजापुर के जिस भोपालपटनम में एक जुलाई को जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया, वहीं से शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि यह केंद्रीय स्कूल है। इस स्कूल के दो कमरों में ही पांच कक्षाएं संचालित हैं, जिनमें 96 छात्र पढ़ रहे हैं और एक ही शिक्षिका पढ़ाने वाली हैं।

प्रभारी प्राचार्या पर ही पढ़ाने की भी जिम्मेदारी

भोपालपटनम नगर के रानी दुर्गावती वार्ड के एक जर्जर भवन के दो कमरों में सीबीएसई गवर्मेंट इंग्लिश स्कूल संचालित हो रहा है। स्कूल की व्यवस्था और पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर यहां अध्यनरत 15 छात्रों ने टीसी लेने की मंशा जाहिर की हैं। अभिभावक नहीं चाहते कि उनके बच्चों का भविष्य खराब हो। इस जर्जर भवन के दो कमरों संचालित स्कूल के एक कमरे में पहली से तीसरी व दूसरे कमरे में चौथी से पांचवी तक कि कक्षाएं लगती हैं। स्कूल में महज एक प्रभारी प्राचार्या है। जिनके पास बच्चों को पढ़ाने की भी जिम्मेदारी है।

दो शिक्षक पदोन्नत होकर गए, दो को मूल संस्था में भेजा

प्राचार्या बबिता चंद्राकर ने बताया कि स्कूल में पिछले सत्र में पांच शिक्षक पदस्थ थे। इनमें दो शिक्षक पदोन्नत होकर दूसरी संस्था चले गए। वहीं अन्य दो शिक्षकों को उनकी मूल संस्था भेज दिया गया। इसके बाद से यहां शिक्षकों की पदस्थापना नहीं कि गई हैं। बताया कि यहां पहली क्लास में सात, दूसरी में 25, तीसरी में 26, चौथी में 17 और पांचवीं क्लास में 21 बच्चे अध्यनरत हैं। जबकि छठवीं से लेकर आठवीं तक कि क्लास रालापल्ली स्थित स्कूल में संचालित हो रही हैं। वहां पर 3 शिक्षक पदस्थ किए गए हैं।

अफसर बोले- दो दिन में हो जाएगी व्यवस्था

वहीं स्कूल की हालत भी जर्जर है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। ऐसे में दीवारों से गिरता प्लास्टर खतरा बना रहता है। दूसरी ओर ब्लाक एजुकेशन ऑफिसर कंडिक नारायण ने कहते हैं कि सीबीएसई स्कूल में आगामी 15 जुलाई तक शिक्षकों की व्यवस्था कर दी जाएगी। इसके लिए पांच जुलाई को एसएमडीसी के मेम्बर ने आवेदन दिया था। इसी के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी को शिक्षक व्यवस्था के लिए प्रस्ताव भेजा गया हैं। वहीं भवन की वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही हैं।

अंडरब्रिज की मांग को लेकर गडकरी को लिखा पत्र जवाब नहीं मिलने पर नाराज, किया चक्काजाम

कोरबा। कोरबा-चांपा हाईवे के बीच अंडर ब्रिज की मांग को लेकर ग्रामीण नाराज हो गए हैं। अपनी आवाज बुलंद करने के लिए ग्राम पताड़ी के ग्रामीणों ने कोरबा-चांपा मुख्य मार्ग में चक्का जाम कर दिया है, जिसकी वजह से कोरबा-चांपा मुख्य मार्ग में आवाजाही बंद हो गई है। चक्काजाम की सूचना पर प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है।

नितिन गडकरी को ग्रामीणों ने लिखी चिट्ठी

बताया जाता है कि ग्रामीण अंडर ब्रिज की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा था। लेकिन अब तक पत्र का जवाब नहीं आया है। ग्रामीणों की मांग है कि उनके बच्चों के जाने आने के लिए बीच रास्ते में एक अंडर ब्रिज दिया जाए। ताकि बच्चों को घूमकर स्कूल न जाना पड़े। वहीं ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम कर दिया है।

आधे घंटे रहा चक्का जाम

उरगा थाना प्रभारी युवराज तिवारी ने बताया कि ग्रामीण अंडर ब्रिज की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया था। जहां घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उच्चाधिकारियों के आश्वासन के बाद चक्का जाम समाप्त किया गया। लगभग आधा घंटे तक चक्का जाम की स्थिति निर्मित रही। जिससे बहाल कर लिया गया है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

शीश महल में रहकर कुछ लोग शीर्षासन में व्यस्त हैं : अनुराग

नईदिल्ली। दिल्ली की स्थिति को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्य के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि शीश महल में रहकर कुछ लोग शीर्षासन में कुछ लोग व्यस्त हैं। वे अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि हमने पिछले 9 वर्षों में कोई ज़िम्मेदारी उठाते नहीं देखा लेकिन दोष लगाते हुए देखा है... जो दिल्ली को पेरिस बनाने की बात करते थे, 300 झील बनाने की बात करते थे आज गली-गली तलाब बने हैं। लोग अलग-अलग मीम बना रहे हैं। दरअसल, भाजपा दिल्ली के मुख्यमंत्री पर अपने आवास में करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप लगाती है। इसको लेकर जांच भी चल रही है। दिल्ली की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को रविवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों को राहत शिविर में तब्दील किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के मंत्री जमीन पर दिखाई दे रहे हैं।

कोर्ट ने केजरीवाल और संजय को 26 को पेश होने को कहा

अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयानों से संबंधित आपराधिक मानहानि के मामले में अहमदाबाद की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को 26 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया है। आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। यहां की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने पूर्व में दोनों नेताओं को गुरुवार (13 जुलाई) को पेश होने का निर्देश दिया था। लेकिन, उनके वकील ने छूट संबंधी आवेदन दायर कर कहा कि केजरीवाल और सिंह दिल्ली में भारी बारिश के कारण पेश नहीं हो सके। गुजरात विश्वविद्यालय के वकील अमित नायर ने याचिका का विरोध नहीं किया, लेकिन अदालत से आग्रह किया कि आप नेताओं को अगली तारीख पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाए क्योंकि मुकदमे में देरी हो रही है।

नीतीश और लालू विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली दूसरी संयुक्त विपक्ष की बैठक में भाग लेंगे। जनता दल-यूनाइटेड (जेडी-यू) के वरिष्ठ नेता और बिहार के मंत्री संजय कुमार झा ने इस बात की जानकारी दी है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए, झा ने कहा कि पटना में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विरोधी 15 दलों के प्रमुखों की उपस्थिति वाली पहली मेगा विपक्षी बैठक का परिणाम सकारात्मक रहा। बेंगलुरु 18 में संयुक्त विपक्ष की दूसरी बैठक में कुल 24 दलों के शामिल होने की संभावना है। बेंगलुरु बैठक में शामिल होने वाले बिहार के अन्य प्रमुख लोगों में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी शामिल हैं। राजद छह-दलीय महागठबंधन सरकार में एक प्रमुख घटक है। बेंगलुरु बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के भी शामिल होने की संभावना है।

जयंत चौधरी को मनाने की भाजपा की कोशिश नाकाम

लखनऊ। जयंत चौधरी को पटाने की भाजपा की कोशिशें नाकाम हो गई हैं और वे विपक्षी दलों की बेंगलुरु बैठक में हिस्सा लेने के लिए 17-18 जुलाई को कर्नाटक पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच बढ़ती दूरियों के बीच भाजपा कोशिश कर रही थी कि छोटे चौधरी उसके पाले में आ जाएं और पार्टी के मिशन 80 को सफल बनाने में अपना योगदान दें। लेकिन फिलहाल छोटे चौधरी ने विपक्षी खेमे में ही रहने का निर्णय किया है। विपक्षी दलों की एकता के बीच माना जा रहा है कि कुछ राज्यों में भाजपा को सीटों का नुकसान हो सकता है। इसमें बिहार, महाराष्ट्र से लेकर प. बंगाल तक के राज्य शामिल हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए मजबूत गढ़ के रूप में उभरा है। लेकिन वह अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करने के लिए जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। राजभर उसको पूर्वांचल में मजबूत करने में मदद कर सकते हैं तो जयंत चौधरी पश्चिम में जाट वोटों को एकजुट करने में भाजपा को सहयोग कर सकते हैं।

हाईकोर्ट ने नवाब मलिक की जमानत याचिका खारिज की

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार चल रहे नवाब मलिक ने हाईकोर्ट से स्वास्थ्य आधार पर जमानत मांगी थी लेकिन मलिक की याचिका खारिज करते हुए आदेश दिया कि वो दो सप्ताह के बाद योग्यता के आधार पर जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। नवाब मलिक ने 30 नवंबर, 2022 के विशेष अदालत द्वारा खारिज की गई जमानत याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में नवाब मलिक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई के सामने तर्क पेश किया कि उनके याचिकाकर्ता नवाब मलिक का स्वास्थ्य पिछले आठ महीनों में बेहद खराब हो गया है और गिरफ्तारी के बाद उनकी किडनी की समस्या भी बढ़ गई थी।

भाजपाइयों पर लाठीचार्ज के बाद भाजपा अध्यक्ष बोले-

चार्जशीटेड व्यक्ति को बचाने में नीतीश नैतिकता भूले : नड्डा

पटना। पूर्व घोषित विधानसभा मार्च के दौरान पटना में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले दागने और लाठीचार्ज करने की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि चार्जशीटेड व्यक्ति को बचाने में सीएम नैतिकता भूल चुके हैं।

भाजपा के विधानसभा मार्च के दौरान पटना पुलिस के लाठीचार्ज में भाजपा नेता की मौत के बाद सिसायत गरमा गई है। भाजपा नेताओं ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और इस घटना को लोकतंत्र की हत्या बता दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर पटना में हुए लाठीचार्ज राज्य सरकार की विफलता और बौखलाहट का नतीजा है। महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार के क़िले को बचाने के लिए लोकतंत्र पर हमला कर रही है।जिस व्यक्ति पर चार्जशीट हुई है, उसको बचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री अपनी नैतिकता तक भूल गये हैं।

क्रूरता पुर्ण तरीके से भाजपा पदाधिकारी की हत्या कर दी गई

वहीं बिहार भाजपा के सह प्रभारी और सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन, बिहार की ठगबंधन की सरकार के कुशासन के खिलाफ बिहार भाजपा द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से किये जा रहे विधानसभा मार्च पर बिहार पुलिस द्वारा क्रूरता पुर्ण तरीके से भाजपा पदाधिकारी की हत्या कर देना बताता है कि बिहार में जंगलराज का साम्राज्य है। इस अत्याचार का जबाब बिहार की जनता देगी।

ये कौन सी महागठबंधन सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है

बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि आखिर ये कौन सी महागठबंधन सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठी तानने की अनुमति है। नीतीश बाबू आपके अंदर उपजे भय का प्रमाण है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के किले को बचाने के लिए अंधी, बहरी और गूंगी ठगबंधन की सरकार लाठी और गोलों के जोर पर पूरे बिहार को हांकना चाहती है। चच्चा-भतीजा की जोड़ी ये जान ले, बिहार संपूर्ण क्रांति की भूमि रही है, अंहकारी और दम्भी सरकार को देश में नहीं चलने दिया था।लाठी के दम पर बिहार नहीं चलेगा!

आंदोलन को निर्मम तरीके से कुचलने कोशिश की गई

पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि भाजपा के आंदोलन को निर्मम तरीके से कुचलने कोशिश की गई। हमारे एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। पटना की लाठीचार्ज में उनके सिर में गंभीर चोट लगी। सुशील मोदी ने कहा कि पटना पुलिस लाठीचार्ज के बाद भी नहीं रुकी, भाजपा नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हम इन गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं है। हम बिहार की बेहतरी के लिए लड़ते रहेंगे। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमलोग शांतिपूर्व तरीके से आगे बढ़ रहे थे इतने में पुलिसकर्मी लाठी बरसाने लगे। भाजपा के आंदोलन से बिहार सरकार डर गई है।

तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा ने विधानसभा के बाहर और अंदर जमकर हंगामा किया

पटना। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा ने विधानसभा के बाहर और अंदर जमकर हंगामा किया। सदन के शुरू होते ही भाजपा विधायक वेल में पहुंच गए और वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि जनता ने आप लोगों को इसलिये सदन में नहीं भेजा है कि आप हंगामा करें। भाजपा विधायकों को पहले आसन की ओर से अपने अपने जगह पर जाने को कहा गया। लेकिन जब उनका हंगामा जारी रहा तो विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर मार्शलों ने जीवेश मिश्रा और इंजीनियर शैलेन्द्र को ने सदन से बाहर कर दिया। जिसके बाद सदन में मौजूद तमाम भाजपा विधायकों ने वॉकआउट कर दिया और सदन के पोर्टिको में धरने पर बैठ गए। बिना विपक्ष पहली बार मानसून सत्र में प्रश्न काल पूरा हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सदन से निकल गए। 12:45 तक सदन की कार्यवाही विपक्ष के बिना ही चली। इसके बाद अध्यक्ष ने सभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दरअसल, आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने नीतीश सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरते हुए आसन के समक्ष वेल में आकर प्रदर्शन करना शुरू किया। भाजपा विधायक कुर्सी पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। भाजपा विधायक लगातार सदन में तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी के नारे लगा रहे थे। इस पूरे प्रकरण के बाद बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने घोषणा की और कहा कि जिन लोगों ने सदन के अंदर कुर्सियां तोड़ी हैं या गलत आचरण किया है, वीडियो के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पर संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने गंभीर आपत्ति जताई। वहीं, सदन में हो रहे हंगामा पर पहले संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपनी आपत्ति जताई। विजय चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष को पूरे हंगामे पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य लगातार सदन का अपमान कर रहे हैं। सदन की मर्यादा का हनन कर रहे हैं। भाजपा के सदस्यों का सदन में कुर्सी चलाना, टेबल पलटना, मार्शल से भिड़ना उचित नहीं है। सरकार चाहती है कि आप उचित कार्रवाई करें। इस पर विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि भाजपा के सदस्य विपक्ष के रूप में जिस तरह का आचरण कर रहे हैं, वह उचित नहीं है।

कांग्रेस ने मंत्रालयों के प्रचार फंड को सीबीसी को सौंपने का लगाया आरोप

सरकार ने संसद द्वारा पारित बजट की पवित्रता को कम कर दिया

नईदिल्ली। कांग्रेस ने गुरुवार को मोदी सरकार पर प्रचार के लिए संसद द्वारा विभिन्न मंत्रालयों को आवंटित 40 प्रतिशत धनराशि हड़पने और उसे केंद्रीय संचार ब्यूरो को सौंपने का आरोप लगाया और पूछा कि क्या यह दुरुपयोग नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि ऐसा करके सरकार ने संसद द्वारा पारित बजट की पवित्रता को कम कर दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार को पीएम मोदी के अधीन केंद्रीय प्रचार मशीन भी करार दिया। उन्होंने कहा कि संसद भारत सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों के लिए बजट पर मतदान करती है और प्रत्येक कार्यक्रम/योजना का एक अलग बजट प्रमुख होता है।

रमेश ने कहा कि एक अभूतपूर्व कदम में, वित्त मंत्रालय ने 19 मई को आदेश दिया कि विभिन्न विभागों या मंत्रालयों में विज्ञापन और प्रचार के लिए संसद द्वारा मतदान किए गए धन का 40 प्रतिशत केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) के निपटान में रखा जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय के आदेश को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि संसद द्वारा अनुमोदित 2023-24 के लिए सीबीसी का बजट 200 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय के 19 मई के आदेश से चालू वर्ष के लिए सीबीसी का बजट बढ़कर 750 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि स्पष्ट रूप से यह सीबीसी (सीबीआई और ईडी के साथ) 2024 के लिए मोदी सरकार के चुनाव अभियान का अगुआ होगा। सीबीसी पीएम उर्फ प्रचार मंत्री की धुन पर नाचने वाला एक सुपर जार है। लेकिन इस प्रचार मशीन के पास पर्याप्त धन नहीं था। जयराम रमेश ने ट्विटर पर पूछा कि अब इस सर्जिकल स्ट्राइक के साथ, कर्नाटक में सरकार द्वारा हटाए गए 40 प्रतिशत कमीशन की तरह, मोदी सरकार ने संसद द्वारा मंत्रालयों को पहले से आवंटित धन का 40 प्रतिशत हड़प लिया और सीबीसी को समृद्ध किया। क्या यह वास्तव में दुरुपयोग नहीं है?

शीला दीक्षित के घर में किराए पर शिफ्ट होंगे राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास आखिरकार अपना खुद का घर हो सकता है और इसका उनकी पार्टी से ऐतिहासिक जुड़ाव है। वायनाड के पूर्व सांसद - उन्हें मोदी उपनाम मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था, वह अपनी मां सोनिया गांधी के साथ राजधानी में उनके 10 जनपथ स्थित घर पर रह रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वह पिछले कुछ समय से एक घर की तलाश में थे। अब ऐसा लगा रहा है कि उनकी तलाश सफल हो गई है। ऐसी खबरें सामने आई हैं कि पूर्व कांग्रेस नेता जल्द ही एक साधारण तीन बेडरूम वाले घर में रहने वाले हैं और यह किसी और का नहीं बल्कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का है, जिन्होंने अपने जीवन के आखिरी साल वहां बिताए थे। राहुल गांधी दक्षिण दिल्ली के हरे-भरे निज़ामुद्दीन पूर्वी इलाके में हुमायूँ के मकबरे के नजदीक 1,500 वर्ग में फैले तीन-बीएचके आवास में शिफ्ट हो सकते हैं। यह घर दिग्गज कांग्रेस नेता शीला दीक्षित के परिवार का है, जो 1991 से 1998 तक वहां रही। 2015 के बाद वह फिर से उसी फ्लैट में शिफ्ट हो गईं और 2019 में उनका वहीं निधन हो गया।

खेल
प्रमुख समाचार

वर्ल्ड चैंपियनशिप में अगुआई करेंगी मीराबाई चानू

ग्रेटर नोएडा। स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू सितंबर में सऊदी अरब के रियाद में होने वाली विश्व भारोत्तोलन चैम्पियनशिप में फिर भारतीय चुनौती की अगुआई करेंगी। दो बार की पदक विजेता चानू (49 किग्रा) के अलावा राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता बिंदियारानी देवी (55 किग्रा) और अचिंता शेयुली (73 किग्रा), शुभम टोडकर (61 किग्रा) और नारायण अजीत (73 किग्रा) भी इस विश्व प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। टोडकर को छोड़कर यही टीम एशियाई खेलों में भाग लेगी। मई में एशियाई चैम्पियनशिप में छठे स्थान पर रहने के बाद यह तोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता चानू की पहली प्रतियोगिता होगी। चानू और बिंदियारानी इस समय पूर्व भारोत्तोलक से फिजियोथेरेपिस्ट और 'स्ट्रेंथ एंव कंडिशनिंग' कोच बने डा आरोन होर्शिंग के मार्गदर्शन में 65 दिन के शिविर के लिए अमेरिका में हैं। राष्ट्रीय कोच विजय शर्मा भी इस वक्त अमेरिका में हैं, उन्होंने पीटीआई से कहा, ''मीरा चोटिल नहीं है, हम उसके मजबूत पक्षों पर काम कर रहे हैं। वह विश्व चैम्पयनशिप और एशियाई खेलों में हिस्सा लेंगी। '' विश्व चैम्पियनशिप और एशियाई खेलों के बीच काफी कम समय का अंतर है। विश्व चैम्पियनशिप आमतौर पर साल के अंत में नवंबर और दिसंबर में कराई जाती है, लेकिन इस बार यह चार सितंबर से शुरु हो रही है और एशियाई खेल 20 दिन के अंदर चीन के हांगझोउ में 23 सितंबर से शुरु होंगे। एशियाई खेल 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाइंग टूर्नामेंट नहीं है और चानू के पदकों में केवल एशियाड पदक की कमी है। पूर्व विश्व चैम्पियन चानू पिछले साल दिसंबर में विश्व चैम्पियनशिप के पिछले चरण में एक रजत पदक जीता था। लेकिन 2024 ओलंपिक क्वालीफिकेशन नियम के अंतर्गत 2023 विश्व चैम्पियनशिप और 2024 विश्व कप में हिस्सा लेना अनिवार्य है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 165 अंक चढ़ा निफ्टी 19400 के पार

नई दिल्ली। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार रिकॉर्ड बढ़त के बाद फिसलकर बंद हुआ। गुरुवार को सेंसेक्स 164.99 (0.25%) अंकों की गिरावट के बाद 65,558.89 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 29.45 (0.15%) अंकों की गिरावट के साथ 19,413.75 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। हालांकि बंद होने से पहले बाजार पहली बार 66000 के पार पहुंचने में सफल रहा और इसमें 670 अंकों की बढ़त दिखी। इस दौरान निफ्टी भी 19500 के लेवल को पार कर अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। अमेरिका में महंगाई के राहत भरे आंकड़ों के कारण बाजार को बढ़त हासिल करने में मदद मिली। गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार के लिए एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर इतिहास का हिस्सा हो गए। एचडीएफसी बैंक से मर्जर के बाद अब बाजार में एचडीएफसी बैंक नाम से ही शेयरों की ट्रेडिंग होगी।

फेडरल बैंक का नेट प्रॉफिट 29% बढ़कर 854 करोड़ हुआ

नईदिल्ली। फेडरल बैंक का चालू वित्त वर्ष की जून में समाप्त पहली तिमाही का नेट प्रॉफिट 29 फीसदी बढ़कर 854 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। डूबा कर्ज घटने से बैंक का मुनाफा बढ़ा है। दक्षिण के इस निजी क्षेत्र के बैंक ने एक साल पहले की समान तिमाही में 661 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया था। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बैंक ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल आय बढ़कर 5,757 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 4,081 करोड़ रुपये रही थी। समीक्षाधीन अवधि में बैंक की ब्याज आय 3,629 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,025 करोड़ रुपये हो गई। बैंक की संपत्ति की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। जून, 2023 के अंत तक बैंक की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां घटकर 2.38 फीसदी पर आ गईं, जो जून, 2022 में 2.69 फीसदी पर थीं।

चैट जीपीटी को टक्कर देने मस्क ने लॉन्च की एक्सएआई कंपनी

न्यूयॉर्क। टेस्ला के सीईओ और ट्विटर के मालिक ईलॉन मस्क ने बुधवार को अपने लंबे समय से चर्चित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप एक्सएआई को लॉन्च किया। गुगल, माइक्रोसाफ्ट और ओपन एआई सहित टॉप अमेरिकी तकनीकी फर्मों के इंजीनियरों से बनी एक टीम के साथ मिलकर एलन मस्क चैट जीपीटी जैसा टूल बनाना चाहते हैं। मस्क की इस कंपनी का उद्देश्य दुनिया की वास्तविक प्रकृति को समझना है। स्टार्टअप को ईलॉन मस्क लीड करेंगे, जिन्होंने कई मौकों पर कहा है कि एआई के विकास को रोक दिया जाना चाहिए और इस क्षेत्र को रेगुलेशन की आवश्यकता है। मस्क ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा, 'वास्तविकता को समझने के लिए एक्सएआई के गठन की घोषणा की जा रही है।' वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, एक्सएआई 14 जुलाई को एक ट्विटर स्पेस इवेंट आयोजित करेगा।

विदेश व्यापार में कमजोरी चीन का एक्सपोर्ट जून में घटा

बीजिंग। चीन का निर्यात जून में सालाना आधार पर 12.4 प्रतिशत घट गया। दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों के मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने के बाद मांग कमजोर पड़ने से चीन के निर्यात में गिरावट आई है। चीन में गुरुवार को जारी सीमा शुल्क आंकड़ों के मुताबिक आयात में 6.8 प्रतिशत की गिरावट आई है। विदेश व्यापार में कमजोरी से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। इस साल जनवरी-जून में आयात और निर्यात सहित चीन का कुल व्यापार सालाना आधार पर लगभग पांच प्रतिशत घट गया। इस दौरान निर्यात में 3.2 प्रतिशत की गिरावट हुई जबकि आयात 6.7 प्रतिशत घटा। सुरक्षा संबंधी कारणों और चीनी औद्योगिक नीति को लेकर बीजिंग के साथ वाशिंगटन के विवाद से भी व्यापार प्रभावित हुआ है।

चंद्रयान से अंतरिक्ष में आगे बढ़ता भारत

गौहर रजा

चंद्रयान-2 अभियान को नाकाम कहा जाता है, मगर एक वैज्ञानिक के तौर पर मैं ऐसा नहीं मानता। विज्ञान में नाकामी जैसी कोई चीज नहीं होती। हम सीख कर सीढ़ी के अगले पायदान की ओर बढ़ते हैं। चंद्रयान-3 उसी दिशा में एक नया पायदान है। इस अभियान के उद्देश्य वही हैं, जो पिछले अभियान के थे यानी चांद के वातावरण को देखना, वहां होने वाली भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करना और वहां संभावित खनिज पदार्थों का पता लगाना। पहली उपलब्धि तो चांद पर पहुंचने से ही हो जाती है। दूसरी उपलब्धि सॉफ्ट लैंडिंग की होगी, ताकि चंद्रमा पर लैंड करने के बाद उपकरणों का इस्तेमाल कर जानकारियां जुटायी जा सकें। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और सतह पर रोवर उतारना भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नये तरह की उपलब्धि होगी।

भारत ने पिछली सदी के 50 और 60 के दशक में अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में शुरुआती कदम बढ़ाये थे। आज हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। आज खास तौर से भारत के दो प्रक्षेपण यान, पीएसएलवी और जीएसएलवी, बहुत ही भरोसेमंद हैं। इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। विज्ञान छिपा कर रखने की चीज नहीं है। गलतियां होती हैं और उनसे सीख कर हम आगे बढ़ते हैं। आज भी सफल प्रक्षेपणों के प्रतिशत के हिसाब से दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतरीन है। हमारे 90 प्रतिशत से ज्यादा प्रक्षेपण सफल रहे हैं। आज के वक्त में प्रक्षेपण यानों पर भारत की महारत का काफी सम्मान किया जाता है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत दूसरों के मुकाबले कम खर्च में लॉन्च भी करता है और उसके कामयाब रहने की संभावना भी ज्यादा रहती है।

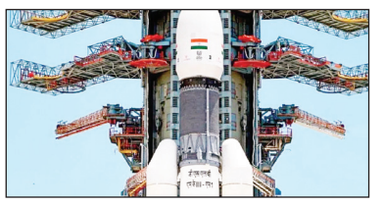

भारत इन यानों के लिए लिक्विड और सॉलिड दोनों तरह के ईंधन भी खुद बना लेता है। अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी संख्या में छोटे उपग्रहों को ले जाकर उन्हें सही कक्षा में रखना एक मुश्किल तकनीक मानी जाती है। वैसे ही, भारी उपग्रहों को सही कक्षा में रखना भी एक अलग तरह का कौशल माना जाता है। भारत ने दोनों ही तकनीकों को साध लिया है। उपग्रहों को भेजने के ऐसे अभियान चलते रहते हैं, मगर अब भारत का अगला सबसे बड़ा अभियान मानव अभियान है। ऐसी उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक उसकी तैयारियां पूरी हो जायेंगी और भारत जल्दी ही मानव को अंतरिक्ष में भेज पायेगा। वह भारत के अंतरिक्ष इतिहास में मील का एक बड़ा पत्थर साबित होगा। हालांकि, चीन इस मामले में भारत से आगे निकल चुका है और वह लगातार इंसानों को अंतरिक्ष में भेज रहा है। भारत को चीन से भी सीखना चाहिए, क्योंकि विज्ञान में दुश्मनी नहीं होती।

अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आर्थिक अवसरों की काफी चर्चा होती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले वर्षों में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जायेगा, मगर यह समझना जरूरी है कि विज्ञान की बुनियादी समझ के बिना कुछ भी नया करना मुश्किल है। बल, गति, वेग, और संवेग को समझे बिना न साइकिल बन सकती है, न मोटर और न रॉकेट। दरअसल, हम जब विज्ञान सीखते हैं, तो हम दूसरे मुल्कों में होने वाली तकनीकी प्रगति को समझ भी पाते हैं। वे हमारी बात समझते हैं, हम भी उनकी बात समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए, अफगानिस्तान जैसे मुल्क में लोग अंतरिक्ष विज्ञान की चर्चा होने पर समझ ही नहीं सकते कि क्या बात की जा रही है। भारत में विज्ञान को समझने वाला एक मजबूत समुदाय मौजूद रहा है, जो विज्ञान को समझ सकता है और आगे भी बढ़ सकता है। अंतरिक्ष विज्ञान का फायदा यहीं से मिलना शुरू हो जाता है, मगर मेरा मानना है कि हमें हर समय तत्काल लाभ की बात नहीं करनी चाहिए। विज्ञान में महारत हासिल हो जाए, तो लाभ अपने आप चला आता है। आज वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी दो से तीन प्रतिशत के बीच बतायी जाती है। वर्ष 2020 में यह 2.1 प्रतिशत या 9.6 अरब अमेरिकी डॉलर थी। चीन की तुलना में यह बहुत कम है। पिछले वर्ष, चीन ने हर महीने लगभग तीन प्रक्षेपण किये।

शिंदे सरकार के अस्थिर होने का खतरा नहीं

हरीश गुप्ता

ऐसी अटकलें लगाने वालों की कमी नहीं है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को उम्मीद से जल्दी अयोग्य ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सौंपने का फैसला किया था क्योंकि दल-बदल विरोधी कानून के तहत पहले निर्णय लेना विधानसभा अध्यक्ष का कर्तव्य है। स्पीकर द्वारा निर्णय सुनाए जाने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट कोई कदम उठाएगा। शिंदे और उनके गुट को अयोग्य घोषित किए जाने की स्थिति में, देवेंद्र फडणवीस की मुख्यमंत्री के रूप में वापसी के अवसर खुल सकते हैं, जो एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद 2019 में बस चूक गए थे। राकांपा नेता अजित पवार का यह पद संभालने का सपना भी सच हो सकता है। राकांपा नेता अतीत में चार बार उपमुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं और अपने मुख्यमंत्रियों के लिए भाग्यशाली साबित नहीं हुए हैं; चाहे वह अशोक चव्हाण हों, पृथ्वीराज चव्हाण हों, देवेंद्र फडणवीस या फिर उद्धव ठाकरे। अगर अजित पवार के पिछले रिकॉर्ड के संकेतों को मानें तो शिंदे का भी वही हश्र होने का डर है। लेकिन दिल्ली में भाजपा आलाकमान स्पष्ट है कि वह महाराष्ट्र में क्या करना चाहता है। यदि भाजपा आलाकमान से आने वाली रिपोर्टों की मानें तो वह एकनाथ शिंदे जैसे सहयोगी को छोड़ने के बजाय नवंबर-दिसंबर में पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद ही कोई फैसला करना पसंद करेगा। आलाकमान की सोच का एक सुराग तब सामने आया जब स्पीकर नार्वेकर ने उम्मीद जताई कि 'सर्वोच्च न्यायालय उनसे एक निश्चित समय सीमा के भीतर शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने के लिए नहीं कहेगा क्योंकि यह विधायिका के काम में न्यायिक हस्तक्षेप होगा।' यह एक स्पष्ट संकेत है कि नार्वेकर एक जटिल मुद्दे पर निर्णय लेने में अपना समय लेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद एकनाथ शिंदे को पद पर बने रहने की अनुमति दी थी, इसलिए कि विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना करने से पहले ही उद्धव ठाकरे ने पद छोड़ दिया था। भाजपा की नजर 42-44 लोकसभा सीटों पर है और वह शिंदे सरकार को गिरने से रोकने और इस धारणा को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी कि भगवा पार्टी अपने सहयोगियों को कमजोर करती है। कानून के जानकारों का कहना है कि मामला किसी न किसी बहाने दिसंबर तक खिंच जाएगा। शायद भाजपा बीएमसी चुनावों के दौरान एमवीए और एनडीए के बीच शक्ति परीक्षण करना चाहती है। भाजपा नेतृत्व शरद पवार को और कमजोर करने के लिए नए सहयोगियों को खुश रखेगा। एआईसीसी उन खबरों से अस्थिर है कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल के साथ उपाध्यक्ष पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। हालांकि, राहुल गांधी ने यह कहकर इस योजना पर पानी फेर दिया है कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य कोई प्रमुख पद नहीं संभालेगा। राहुल गांधी का यह भी दृढ़ विचार है कि एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपनी सांगठनिक टीम गठित करने दी जाए। यह अलग बात है कि स्टार प्रचारक के तौर पर प्रियंका गांधी की बढ़ती अपील को देखते हुए उनकी भूमिका बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी पार्टी की जीत में छाप छोड़ी थी।

भारत में ऊर्जा क्षेत्र का कायाकल्प

आर.के. सिंह

पिछले नौ वर्षों के दौरान, मोदी सरकार ने विद्युत क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलावों को संभव बनाया है। निरंतर लोड शेडिंग और बिजली की कमी वाले दिन अब इतिहास हो गए हैं। वर्ष 2014-15 से पहले, बिजली की आपूर्ति में होने वाला घाटा आश्चर्यजनक रूप से 4.5 प्रतिशत था। हालांकि, 2014 में इस सरकार के कार्यभार संभालने के बाद से बिजली उत्पादन क्षमता में 185 गीगावॉट की प्रभावशाली वृद्धि की गई है। इसके साथ भारत बिजली की कमी वाले देश की जगह अधिशेष बिजली वाला देश बन गया है। आज हमारी कुल स्थापित क्षमता 417 गीगावॉट है, जोकि 222 गीगावॉट की चरम मांग से लगभग दोगुनी है। परिणामस्वरूप, भारत अब पड़ोसी देशों को बिजली का निर्यात कर रहा है।

पारेषण (ट्रांसमिशन) के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 2013 के बाद से, लगभग दो लाख सर्किट किलोमीटर तक फैली पारेषण लाइनों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया गया है जो पूरे देश को एक ही आवृत्ति (फ्रीक्वेंसी) पर संचालित होने वाले एक एकीकृत ग्रिड से जोड़ता है। इन पारेषण लाइनों में 800 केवी एचवीडीसी जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया गया है और ये समुद्र तल से 15000/16000 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीनगर - लेह लाइन सहित कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण व दुर्गम इलाकों से होकर गुजरती हैं। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 112 गीगावॉट बिजली स्थानांतरित करने की क्षमता ने भारत को एक एकीकृत बिजली बाजार में बदल दिया है, बिजली स्थानांतरित करने की यह क्षमता 2014 में मात्र 36 गीगावॉट की थी। स्थानांतरण की इस क्षमता की सहायता से वितरण कंपनियों को देश भर में किसी भी उत्पादक कंपनी से प्रतिस्पर्धी दरों पर अधिकतम बिजली खरीदने की सहूलियत मिल गई है। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली मिलने लगी है।

सभी लोगों तक बिजली पहुंचाना इस सरकार के प्रयासों का एक प्रमुख फोकस रहा है। हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले, आज़ादी के 67 साल बाद भी 18,000 से अधिक गांव और कई बस्तियां बिजली से वंचित थीं। अगस्त 2015 में, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 1000 दिनों के भीतर हर गांव को विद्युतीकृत करने के लक्ष्य की घोषणा की थी। पहाड़ी क्षेत्रों और रेगिस्तानी इलाकों में लॉजिस्टिक से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, सरकार ने निर्धारित समय से 13 दिन पहले, केवल 987 दिनों में ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया। इस

उपलब्धि को अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 2018 में ऊर्जा क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण खबर के रूप में मान्यता दी थी।

इस सफलता को आधार बनाकर आगे बढ़ते हुए, सरकार ने हर घर को बिजली से जोड़ने का लक्ष्य रखा। उल्लेखनीय तरीके से, यह लक्ष्य 18 महीनों के भीतर ही हासिल कर लिया गया और कुल 2.86 करोड़ घरों को बिजली से जोड़ा गया। बिजली पहुंचाने की दिशा में यह तेज प्रसार ऊर्जा क्षेत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है, जिसे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी से मान्यता मिली है। मोदी सरकार की नीति यह सुनिश्चित करने की है कि कोई भी पीछे न छूटे।

वितरण प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से, सरकार ने सभी राज्यों में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृत लागत से व्यापक योजनाएं लागू कीं। इन योजनाओं में नए सबस्टेशनों का समावेश करना, मौजूदा सबस्टेशनों को उन्नत करना, ट्रांसफार्मर की स्थापना और हजारों किलोमीटर लंबी एलटी व एचटी लाइनों का निर्माण एवं उन्हें बदलना शामिल था। इन प्रयासों की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की औसत उपलब्धता 2015 में 12 घंटे से बढ़कर आज 22.5 घंटे हो गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में अब औसतन 23.5 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। परिणामस्वरूप, डीजी सेट का बाज़ार अब समाप्त हो गया है!

सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा पर अपना ध्यान केन्द्रित करके पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित की है। वर्ष 2015 में, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 2022 तक 175 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य की घोषणा की थी। वर्तमान में, कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के तहत अतिरिक्त 84 गीगावॉट के साथ भारत ने 172 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की है। इस विकास ने भारत को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले देश के रूप में स्थापित किया है। अपनी इस ख्याति के कारण भारत ने दुनिया भर के प्रमुख कोषों से निवेश को आकर्षित किया है। इसके अलावा, भारत ने निर्धारित समय से नौ साल पहले ही 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 40 प्रतिशत बिजली उत्पादन क्षमता की अपनी प्रतिबद्धता हासिल कर ली है। वर्तमान में, स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 43 प्रतिशत हिस्सा यानी कुल 180 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आता है।

सरकार उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने में भी सफल रही है। वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में उत्सर्जन की तीव्रता को 33 प्रतिशत - 35 प्रतिशत तक कम करने के लक्ष्य को हासिल करके, भारत ने खुद को वैश्विक तापमान में 2-डिग्री से कम वृद्धि करने के विचार के अनुरूप चलने वाले एकमात्र जी-20 देश और प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है, उजाला (एलईडी वितरण), 'प्रदर्शन करें, उपलब्धि हासिल करें और व्यापार करें' [परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (पीएटी)], उपकरणों के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम और ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जैसे विभिन्न कार्यक्रमों ने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रति वर्ष 159 मिलियन टन की कमी लाने में योगदान दिया है। व्यावसायिक और आवासीय भवनों में ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य से तैयार किया गया बिल्डिंग कोड इस दिशा में एक और बड़ा कदम है। हमने अब 2005 के स्तर के मुकाबले 2030 तक अपने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को एक बिलियन टन और हमारी अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करने का संकल्प लिया है। इन लक्ष्यों को भी हम 2030 से पहले हासिल कर लेंगे।

संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में व्यापक सुधार लागू किये गये हैं। वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) में दक्षता और वित्तीय अनुशासन में सुधार लाने हेतु वित्तपोषण को एटीएंडसी संबंधी नुकसान में कमी के साथ जोड़ना, ऊर्जा लेखांकन और ऑडिट को लागू करना तथा राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, डिस्कॉम कंपनियों का एटीएंडसी संबंधी नुकसान वित्तीय वर्ष 2021 में 22 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2022 में 16.44 प्रतिशत रह गया है। डिस्कॉम कंपनियों के यहां बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों (जेनकॉस) का विरासती बकाया घटकर लगभग आधा - 1.4 लाख करोड़ रुपये से 80 हजार करोड़ रुपये - हो गया है। डिस्कॉम कंपनियों द्वारा ली जाने वाली बिजली के लिए किया जाने वाला वर्तमान भुगतान अद्यतन है।

सबसे कुशल उत्पादन स्टेशनों को पहले शेड्यूल करने संबंधी लचीलेपन की अनुमति देकर, हमने उपभोक्ताओं के लिए बिजली की लागत कम कर दी है। 'रीयल-टाइम मार्केट' की शुरूआत के जरिए और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अलग-अलग 'टर्म अहेड' और 'डे-अहेड मार्केट' स्थापित करके बिजली के बाजार का विस्तार भी किया गया है। ऊर्जा रूपांतरण की दिशा में प्रयास के तहत, हमने ताप विद्युत संयंत्रों में तापीय ऊर्जा के साथ नवीकरणीय ऊर्जा की बंडलिंग और बायो-मास को-फायरिंग की अनुमति दी है। 100 किलोवाट या इससे अधिक जुड़े भार वाला कोई भी उपभोक्ता अब ऐसे उत्पादन संयंत्रों से नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। सरकार पीएलआई के जरिए सौर पीवी सेल के उत्पादन और व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण के साथ बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को समर्थन प्रदान कर रही है।

जलविद्युत क्षेत्र, जो मंद पड़ा था, को लगभग 15 गीगावॉट की निर्माणाधीन परियोजना के साथ फिर से सक्रिय किया गया है। विद्युत चालित वाहनों (ईवी) के लिए चार्जिंग संबंधी अवसंरचना स्थापित करने के नियमों व दिशानिर्देशों को सरल बनाया गया है और घरेलू कनेक्शन से चार्जिंग संभव हो गई है। विवाद समाधान तंत्र अब एक महीने के भीतर विवाद का निपटारा करता है।

संक्षेप में, मोदी सरकार ने विद्युत क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव किए हैं। उत्पादन क्षमता के विस्तार, पारेषण (ट्रांसमिशन) नेटवर्क के प्रसार, बिजली को सुलभ बनाने, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और व्यापक सुधारों को लागू करने पर ध्यान देकर भारत ने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। पर्यावरण, ऊर्जा दक्षता और सतत विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता ने भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित किया है। नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में और ऊंचे लक्ष्य तथा उत्सर्जन में और अधिक कटौती करने के इरादे के साथ, मोदी सरकार ने भारत के विद्युत क्षेत्र के भविष्य को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना जारी रखा है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद् (भाग-6)

गतांक से आगे...

तिर्यक, पक्षी एवं चौपायों में यह कन्द अण्डाकार होता है तथा उसका मध्य स्थान नाभि कहा जाता है। इसमें बारह अरों वाला चक्र है, जिसमें विष्णु आदि देवों की मूर्तियाँ स्थित हैं। इस चक्र को मैं (ब्रह्म) अपनी माया से भ्रमाता रहता हूँ। इन बारह अरों में जीव इस तरह से भ्रमण करता रहता है, जैसे मकड़ी अपने जाल में घूमती रहती है। जीव प्राणतत्त्व में आरूढ़ होकर ही विचरण करता है, उसके बिना (वह विचरण) नहीं कर सकता है। उसके ऊर्ध्व में कुण्डलिनी महाशक्ति का तिर्यक् एवं ऊँचा स्थान है।

वह अष्ट प्रकृति स्वरूपा आठ तरह से कुण्डली करके वायु एवं अन्न-जल के संचार को रोकती रहती है। वह कन्द को चारों तरफ से आवृत करके उसके पार्श्व में प्रतिष्ठित है। वह अपने मुख के द्वारा ब्रह्मरन्ध्र के मुख को समवेष्टित किये हुए (घेरे हुए) है। योग के अभ्यास द्वारा यह कुण्डलिनी महाशक्ति वायु के द्वारा जाग्रत् अग्नि की भाँति हृदयरूपी आकाश में नागरूपा, अत्यधिक शुभ्र प्रकाशमय कान्ति से स्फुरित होती रहती है। अपान से दो अंगुल ऊर्ध्व की ओर एवं मेद्र (मूत्रेन्द्रिय) से नीचे मनुष्य के शरीर का मध्य भाग माना गया है तथा चौपायों (पशुओं) का मध्य भाग उनके हृदय प्रदेश में बतलाया गया है। अन्य प्राणियों का मध्य भाग नाभि का मध्य क्षेत्र है, जिसमें विभिन्न नाड़ियाँ समावृत हैं। प्राण एवं अपान से युक्त सुषुम्ना नाड़ी शरीर में चार प्रकार से प्रकाशित होती है।

कन्द के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी प्रतिष्ठित है, वह पद्म सूत्र के सदृश अति सूक्ष्म है तथा सीधी ऊर्ध्व की तरफ प्रवर्तित (गतिशील) हो गई है। ब्रह्मरन्ध्र तक गमन करने वाली यह वैष्णवी ब्रह्मनाड़ी विद्युत् के समान प्रकाश युक्त एवं निर्वाण प्राप्ति की पद्धति वाली है (अर्थात् मोक्ष प्रदान करने वाली है।) उस (सुषुम्ना) के अगल-बगल में इड़ा एवं पिंगला दो नाड़ियाँ प्रतिष्ठित हैं। इड़ा नाड़ी कन्द से निकलकर बायें नासापुट तक गई है और पिंगला उससे निकलकर दाहिने नासापुट तक गई है। गान्धारी तथा हस्तिजिह्वा ये दो नाड़ियाँ भी वहीं पर स्थित हैं। (ये दोनों नाड़ियाँ) उनके आगे-पीछे बाय तथा दायीं आँख तक गई हुई हैं। पूषा तथा यशस्विनी ये दोनों नाड़ियाँ गुदा मूल से निकलकर गमन करते हुए दायें एवं बायें कान तक गई हैं। अलम्बुसा नामक नाड़ी मेद्र स्थान के अन्त तक नीचे की तरफ गई हुई है।

क्रमशः ...

गोपाल गणेश आगरकर

गोपाल गणेश आगरकर का नाम भारत के प्रसिद्ध समाज सेवकों में लिया जाता है। एक पत्रकार के रूप में भी उन्होंने प्रसिद्धि पाई थी। वे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के सहपाठी रहे थे। उन्होंने सुधारक नामक एक साप्ताहिक भी निकाला था। गोपाल गणेश आगरकर वर्ष 1892 में फ़र्ग्युसन कॉलेज, पुणे के प्रधानाध्यापक बनाये गए थे और फिर इस पद पर वे अंत तक रहे।

लोकमान्य बालगंगाधर के सहपाठी और सहयोगी गोपाल गणेश आगरकर का जन्म 14 जुलाई, 1956 ई. को महाराष्ट्र में सतारा ज़िले के तेम्मू नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने पुणे के दक्कन कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। अपने विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने देश और समाज सेवा का व्रत ले लिया था।

आगरकर, लोकमान्य तिलक और उनके सहयोगी यह मानते थे कि शिक्षा-प्रसार से ही राष्ट्र का पुनर्निर्माण संभव है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये जनवरी, 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई। परंतु अपने विचारों के प्रचार के लिये गोपाल गणेश आगरकर जी के पास इतना पर्याप्त नहीं था। 2 जनवरी, 1881 से उन्होंने अंग्रेज़ी साप्ताहिक मराठा का और 4 जनवरी से मराठी साप्ताहिक केसरी का प्रकाशन आरंभ किया।

वर्ष 1894 में दक्कन एजुकेशनल सोसाईटी की स्थापना हुई और दूसरे वर्ष फ़र्ग्युसन कॉलेज अस्तित्व में आया। गोपाल गणेश आगरकर तथा लोकमान्य बालगंगाधर तिलक आदि इस कॉलेज के प्रोफेसर थे।

लोकमान्य तिलक से मतभेद

साप्ताहिक पत्र केसरी के सम्पादन में भी गोपाल गणेश आगरकर, लोकमान्य तिलक के निकट सहयोगी थे, परंतु बाल विवाह और विवाह की उम्र बढ़ाने के प्रश्न पर आगरकर जी का तिलक से मतभेद हो गया। इस मतभेद के कारण 1887 में वे साप्ताहिक पत्र केसरी से अलग हो गये। अब उन्होंने स्वयं का सुधारक नामक नया साप्ताहिक निकालना आरंभ किया। 1890 में लोकमान्य तिलक ने दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी छोड़ दी। आगरकर हिंदू धर्म में रूढ़िवादी प्रथाओं के भी आलोचक थे। दूसरी ओर, तिलक को केसरी में हिंदू धर्म के बारे में आगरकर का कटाक्ष पसंद नहीं आया।

समाज सुधार कार्य

गोपाल गणेश आगरकर 1892 में फ़र्ग्युसन कॉलेज के प्रधानाचार्य नियुक्त किये गए और वे जीवन पर्यंत इसी पद पर रहे। आगरकर बड़े उदार विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने छुआछूत और जाति प्रथा का खुलकर विरोध किया। वे विधवा विवाह के पक्षपाती थे। उनका कहना था कि लड़कों की विवाह की उम्र 20-22 वर्ष और लड़कियों की 15-16 वर्ष होनी चाहिए। 14 वर्ष तक की अनिवार्य शिक्षा और सह शिक्षा का भी उन्होंने समर्थन किया।

सांप्रदायिक एकता के समर्थक

राष्ट्र की उन्नति के लिये सांप्रदायिक एकता को आवश्यक मानने वाले गोपाल गणेश आगरकर ने विदेशी सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति का प्रबल विरोध किया। आर्थिक उन्नति के लिये वे देश का औद्योगीकरण आवश्यक मानते थे। समाज सुधार के कार्यों में विशेष योगदान देने वाले गोपाल गणेश आगरकर जी का निधन 17 जून, 1895 ई. में 43 वर्ष की अल्प आयु में हुआ।

क्या एनडीए में शामिल होंगे जयंत और चंद्रशेखर?

अनिल सिंह

क्या समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी खिचड़ी, पुलाव और बिरयानी का चावल छोड़कर खीर खायेंगे? यह सवाल इसलिए क्योंकि स्वयं जयंत चौधरी ने ट्वीट किया है कि जब चावल ही खाना है तो खीर क्यों ना खाई जाये! दरअसल, उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण में पिछले कुछ समय से जबदरस्त हलचल है। दोस्ती की कसमें खाने वाले दुश्मन हुए जा रहे हैं तो दुश्मनों से गलबहियां करके दोस्ती के तराने गाये जा रहे हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के सामने सबसे मजबूत सपा-रालोद गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों दलों के नेताओं की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं, जिससे लग रहा है कि यह गठबंधन भी जल्द टूट जायेगा। विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन के सामने सपा ने रालोद, सुभासपा एवं अपना दल (कमेरावादी) का मजबूत विकल्प तैयार किया था, लेकिन भाजपा की सत्ता में वापसी के बाद से ही गठबंधन में उठापटक जारी है। सबसे पहले इस गठबंधन से सुभासपा के नेता ओम प्रकाश राजभर ने किनारा किया, अब जयंत चौधरी भी उसी नक्शेकदम पर हैं।

माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी भाजपा खेमे में आ जायेंगे। अंदरखाने जयंत चौधरी सीटों का समीकरण बैठाने में लगे हुए हैं। जयंत को भी साफ नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल रहने से भविष्य

में कोई फायदा नहीं है। सपा प्रदेश की सत्ता से बाहर है, और केंद्र में भी उसका कोई निश्चित भविष्य नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में पक रही गठबंधन खिचड़ी का भविष्य भी स्पष्ट नहीं है। इस गठबंधन से प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर भी रार तय है, इसलिए जयंत चौधरी खिचड़ी, बिरयानी, पुलाव का चावल खाने की बजाय खीर खाना ज्यादा मुनासिब मान रहे हैं। भाजपा को भी इस बेल्ट में सहयोगियों की जरूरत है। नीतीश कुमार के एनडीए से बाहर होने के बाद बिहार भाजपा की सबसे कमजोर कड़ी बन गया है। यूपी-बिहार की 120 सीटों पर एनडीए ने 2014 में 103 तथा 2019 में 105 सीटों पर जीत हासिल की थी, जो उसकी कुल जीती गई सीटों के 30 फीसदी से ज्यादा है। बिहार में होने वाले संभावित नुकसान की भरपायी भाजपा यूपी में अधिक से अधिक सीट जीतकर करना चाहती है।

रालोद और सुभासपा जैसे दलों को अपने साथ जोड़ना भाजपा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और आवश्यक भी। दूसरी तरफ, जयंत चौधरी को भी अपनी पार्टी चलाने के लिये संसाधनों की जरूरत है। संसाधन के बिना पार्टी चलाना आसान नहीं है, और सत्ता में भागीदारी के बगैर संसाधन जुटाना सरल काम नहीं है। खासकर उन दलों के लिए जो निश्चित क्षेत्र में जाति आधारित वोट बैंक की राजनीति करती हैं। खबर है कि भाजपा जयंत चौधरी को अपनी पार्टी में लाकर पश्चिम के जाटलैंड में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है। भाजपा की नजर आजाद पार्टी के चंद्रशेखर पर भी है। पश्चिमी यूपी में जाट और दलित को साध लेने से कई सीटों के समीकरण बदल सकते हैं। भाजपा विधानसभा चुनाव में इस रणनीति का फायदा भी उठा चुकी है। फिलहाल भाजपा की प्राथमिकता जयंत चौधरी हैं। किसान आंदोलन के बाद बदले समीकरण में जाट वोटों में बंटवारा रोकने तथा राजस्थान में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भाजपा रालोद को अपने साथ जोड़ना चाहती है। जाट वोटों के लिये भाजपा ने भूपेंद्र चौधरी को यूपी का अध्यक्ष बनाया तो जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाकर उन्हें खुश करने की कोशिश पहले ही कर चुकी है। भाजपा जयंत चौधरी को प्रदेश तथा केंद्र की सत्ता में भागीदारी देने को तैयार है, लेकिन बात सीटों पर आकर अटक जा रही है। भाजपा केंद्र और प्रदेश में होने वाले संभावित विस्तार में रालोद को भी शामिल करना चाहती है, लेकिन सीटों का समीकरण फाइनल नहीं हो पा रहा है। केंद्र का आखिरी विस्तार भी इसी कारण टलता जा रहा है। फिलहाल सपा गठबंधन में शामिल रालोद ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय ने यूपी की एक दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की बात कह कर पासा फेंक दिया है।

सपा नेतृत्व ने इस बयान पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन पार्टी के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने कहा है कि रालोद के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो केवल अपनी जाति के कुछ वोट इधर से उधर कर सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अब सपा रालोद गठबंधन के टूटने की औपचारिक घोषणा ही बाकी रह गई है। जयंत चौधरी पटना में आयोजित विपक्ष की रैली में आमंत्रण होने के बावजूद नहीं पहुंचे थे, जो संकेत दे रहे हैं कि खीर धीमी आंच पर पक रही है। खबर है कि भाजपा जयंत चौधरी को मथुरा के अलावा एक और सीट के साथ प्रदेश में एक मंत्री और केंद्र में एक मंत्री पद देने को तैयार है, लेकिन जयंत लोकसभा की दो से ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी ठोंक रहे हैं।

यहीं आकर पेंच फंस रहा है। भाजपा रालोद को दो से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी नजर सुभासपा के ओम प्रकाश राजभर पर भी है। यह गठबंधन हो जाता है तो एक सीट उन्हें भी देनी पड़ सकती है। भाजपा किसी भी स्थिति में पांच-छह सीटों से ज्यादा सहयोगी दलों को देने को तैयार नहीं है। अपना दल के पास दो सीटें हैं। भाजपा रालोद को भी दो सीटें देने को तैयार है। सुभासपा के शामिल होने पर उसे गाजीपुर या मऊ की सीट दी जा सकती है। निषाद पार्टी का दावा संतकबीरनगर सीट पर पहले से ही है। नरेंद्र मोदी-अमित शाह की नजर दलित नेता चंद्रशेखर आजाद पर भी है। मोदी और शाह यूपी में सभी 80 सीटें जीतने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसलिए विधानसभा चुनाव में विरोधी रहे दलों को लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी कीमत पर जोड़ना चाहते हैं। अगर पश्चिमी यूपी में जाट के साथ दलित वोट जुड़ जाएं तो इस इलाके में एनडीए को हराना किसी भी दल के लिए मुश्किल होगा।

बापू की दिनचर्या

सायंकालीन प्रार्थना (भाग-3)

गतांक से आगे...

ऐसी थी उनकी ईश्वर-निष्ठा और जीवन-साधना! फिनिक्स आश्रम में प्रार्थना में मानव मात्र को पूर्ण संयत तथा विकार- रहित करने और ऊपर उठानेवाले गीता के कृष्णार्जुन के कथोपकथन रूप में बताए दार्शनिक तत्त्व का पारायण विशेष रूप से होता। दूसरे शब्दों में- गीता के द्वितीय अध्याय के अंतिम उन्नीस श्लोक पढे जाते, जिनमें स्थितप्रज्ञ के लक्षण हैं। बापू के कथनानुसार सत्याग्रही के ये ही लक्षण होने चाहिए। उनकी दृष्टि में स्थितप्रज्ञ और सत्याग्रही— दोनों के लिए यही उपयुक्त साधना है। यह बात नित्य स्मरण रहे, इसीलिए आरंभ से उनकी सायंकालीन प्रार्थना में उन श्लोकों का पारायण होता रहा है। गीता के श्लोकों के बाद वहाँ कुछ गुजराती और हिंदुस्तानी भजन गाए जाते। वहाँ उनके आश्रम में विविध धर्मावलंबी थे, जिनमें गोरे ईसाई भी थे। उनके संतोष की दृष्टि से बापू ने कुछ अंग्रेजी सुभाषित चुने थे, जिन्हें के सबके साथ तन्मय होकर गाते। एक तमिल गीत भी था। इन सबका संग्रह फिनिक्स आश्रम द्वारा नीतिनां काव्य के नाम से प्रकाशित हुआ था। भारत आने पर बापू की सायंकालीन प्रार्थना में गीता के पूर्वोक्त उन्नीस श्लोकों के अतिरिक्त भजन और रामधुन का कार्यक्रम चलने लगा। कभी भजन गाए जाते तो कभी रामचरितमानस के कुछ अंशों का पाठ होता, कभी इस्लाम के धर्मग्रंथों से कुछ अंशों का पारायण होता। साबरमती में जब स्वामी सत्यदेव परिव्राजक आश्रम के आरंभिक दिनों में थे, तब से प्रार्थना में रामचरितमानस का पाठ शुरू हुआ। सेवाग्राम आश्रम में शाम की प्रार्थना में मानस के कुछ अंशों का पारायण ठाकुर बलवंत सिंह के आग्रह से शुरू हुआ। बापू की सायंकालीन प्रार्थना में बौद्ध मंत्र, उपनिषद्-मंत्र, यं ब्रह्मा... वाला श्लोक, गीता अध्याय दो के अंतिम उन्नीस श्लोक, एकादश व्रत, कुरान की आयतें, जरथोस्ती प्रार्थना, भजन और धुन का समावेश रहता। उन दिनों सायंकालीन प्रार्थना के बाद कुरान शरीफ की आयतें पढ़ी जातीं, तो एकाध भाइयों के द्वारा उसका विरोध होता।

क्रमशः ...

भूपेश मंत्रिमंडल में मरकाम और धनेंद्र बनेंगे मंत्री!

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव से सियासी गलियारे में उथल पुथल मची है। मोहन मरकाम की छुट्टी और दीपक बैज की बतौर पीसीसी चीफ ताजपोशी के बाद कैबिनेट में फेरबदल के भी कयास लगाए जा रहे हैं। खुद सीएम बघेल ने भी इसे लेकर संकेत दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देखते रहिए। इंतजार करिए। सियासी सूत्रों के मुताबिक कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। मोहन मरकाम के साथ ही अभनपुर विधायक धनेंद्र साहू के मंत्री बनाए जाने की संभावना है।

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। सूत्रों के मुताबिक स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है।

दिल्ली में आज कांग्रेस की अहम बैठक रखी गई है। सूत्रों के मुताबिक दो मंत्रियों का इस्तीफा लिया जा सकता है और चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किए जाने के संभावना है। सियासी गलियारों में मोहन मरकाम और धनेन्द्र साहू के अलावा एक और नेता को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है।

चुनाव के 4 महीने पहले फेरबदल और पीसीसी चीफ बदलने पर मुख्यमंत्री भूपेश

बघेल ने कहा है कि संगठन में लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी मिलती रहती है। मोहन मरकाम का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। सभी प्रदेशों में बदलाव हो रहे हैं और रायपुर महाअधिवेशन में पारित हुआ था कि 50 परसेंट जो सीटे हैं, वह 50 साल से कम उम्र वालों को मिलनी चाहिए। हमारे यहां शुरुआत हो रही है। दीपक बैज अभी मुश्किल से 42 के हैं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पहले टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया। फिर मोहन मरकाम को हटाकर बस्तर सांसद दीपक बैज को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया। अब जल्द ही भूपेश कैबिनेट के मत्रिमंडल में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। मंत्रिमंडल में फेरबदल और मोहन मरकाम को मंत्री बनाए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देखते रहिए इंतजार करिए। राजनीति के जानकार वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा का कहना है कि किसी को पद से हटाए जाने का मतलब यह नहीं है कि वह काबिल नहीं था। मोहन मरकाम को यदि हटाया गया है तो हो सकता है उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। यह मैसेज देने की कोशिश रहेगी कि यदिआदिवासी समाज से मरकाम को अध्यक्ष पद से हटाया गया है तो उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और मंत्रिमंडल से भी जो मंत्री हटाए जाएंगे इसका यह मतलब नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया। उसके पीछे कई और वजह भी हो सकती है। उनका स्वास्थ्य भी कारण हो सकता है या फिर सत्ता संगठन में तालमेल की कमी या फिर उनके विभाग ने काम में किसी तरह की कमी या फिर कोई और भी वजह हो सकती है।

दीपक बैज को पीसीसी चीफ बनाने पर भाजपा का कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस ने आदिवासी अध्यक्ष को किया यूज एंड थ्रो

रायपुर। दीपक बैज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। एक बार फिर कांग्रेस ने आदिवासी चेहरे को पीसीसी चीफ की कमान दी है।चुनाव के कुछ महीने पहले हुए इस बदलाव को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी कांग्रेस पर एक आदिवासी को यूज एंड थ्रो करने का आरोप लगा रही है। ट्विटर पर बीजेपी नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। सबसे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मोर्चा खोल दिया है।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला किया है।उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष मोहन मरकाम जी लगातार कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुखर रहे। उन्होंने ष्ठख्न समेत भूपेश सरकार के अनेक भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। इस भ्रष्टाचारी सरकार को यह पसंद नहीं आया और साज़िश करके उन्हें पद से हटाया गया है। यह निहायत ही अनुचित है। कांग्रेस के भीतर नाम मात्र का भी आंतरिक लोकतंत्र नहीं बचा है। ख़तरनाक है यह। आदिवासी समाज का अपमान है।

अरुण साव का निशाना यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने ट्वीट कर कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि मोहन मरकाम, कांग्रेस के संविधान के तहत प्राप्त अधिकार का उपयोग करते हुए पार्टी को चलाने का काम कर रहे थे। इस कारण वे दस जनपथ के निशाने पर थे। कांग्रेस के संविधान के विरुद्ध प्रभारी ने पहले तो आदेश निकाल कर इन्हें अपमानित कर दबाने की कोशिश की, फिर भी अपने सम्मान के लिए मुखर रहे मरकाम जी झुके नहीं तो उन्हें इस तरह अपमानित कर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यह निंदनीय है। कांग्रेस में अब मोहन मरकाम को रहना नहीं चाहिए। उन्हें कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए।

दीपक बैज को पीसीसी चीफ बनाने और मोहन मरकाम को पीसीसी चीफ से हटाने पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि प्रदेश में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव के 4 माह पहले हार के डर के कारण एक तरफ भूपेश बघेल को आधी कुर्सी बांटनी पड़ रही है। तो दूसरी तरफ संगठन के अध्यक्ष को बदला जा रहा है। तो इसका मतलब साफ़ है कि 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार सुनिश्चित है। जनता अब कांग्रेस के पौने 5 साल के कुशासन पर कड़ा निर्णय लेने वाली है। प्रदेश में कांग्रेस की ख़स्ताहाल परिस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष बनाये जाने पर दीपक बैज को बधाई। दीपक बैज को कांग्रेस का नया पीसीसी चीफ बनाए जाने पर बीजेपी नेता तुरंत ट्विटर पर एक्टिव हो गए। एक एक कर लगातार कई नेताओं के ट्वीट आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम रमन सिंह के हमले का अब कांग्रेस कैसे जवाब देती है। ये देखने वाली बात होगी।

संक्षिप्त समाचार

15 को प्रदेश भाजपा घोषणा समिति की बैठक होगी

रायपुर। प्रदेश भाजपा घोषणा पत्र समिति के संयोजक, सह संयोजकों की बैठक प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में संपन्न हुई। इस बैठक में घोषणा पत्र निर्माण की प्रक्रिया और तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में संयोजक विजय बघेल, सह संयोजक रामविचार नेताम, अमर अग्रवाल शिवरतन शर्मा और सदस्य चंद्रशेखर साहु उपस्थित थे। प्रदेश घोषणा पत्र समिति की बैठक 15 जुलाई को अपराह्न तीन बजे होगी।

सीजीपीएससी सिविल जज परीक्षा 20 अगस्त को

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सिविल जज भर्ती परीक्षा 2023 की तारीखों की घोषणा करते हुए अधिसूचना जारी की है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है, वे आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर परीक्षा विवरण और कार्यक्रम देख सकते हैं। सीजीपीएससी सिविल जज परीक्षा 2023 रविवार, 20 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक एक ही पाली में आयोजित होने वाली है। सीजीपीएससी भर्ती अभियान का लक्ष्य सिविल जजों के लिए कुल 49 रिक्तियों को भरना है। परीक्षा छत्तीसगढ़ के तीन जिलों बिलासपुर, दुर्ग भिलाई और रायपुर (छत्तीसगढ़) में पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आयोग द्वारा परीक्षा की तारीख से 10 दिन पहले जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि आयोग द्वारा किसी भी उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से कोई अलग प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा।

आगामी खरीफ वर्ष में धान खरीदी के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक 18 को

रायपुर। आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-2024 में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा कर सुझाव देने हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक 18 जुलाई को होगी । यह बैठक छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित सभाकक्ष में दोपहर 1.30 बजे से आहूत की गई है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में मंत्रीगणों के अलावा कृषि, वित्त, राजस्व, सहकारिता, खाद्य विभाग के साथ ही छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन, चिप्स, अपैक्स बैंक और एनआईसी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों एवं फैसलों के कारण विगत चार सालों में किसानों की संख्या और रकबा में लगातार वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन भी तेजी के साथ बढ़ा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर धान खरीदी के साथ-साथ धान का उठाव के कारण धान का निष्पादन आसानी से संपन्न हुआ है।

अनियमित कर्मचारी संगठन बड़े आंदोलन के लिए तैयार

रायपुर। अनियमित कर्मचारियों ने नियमितिकरण समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हैं। कांग्रेस ने अनियमित कर्मचारियों को सरकार बनते ही दस दिनों अंदर नियमित करने का वादा किया था। लेकिन ना तो नियमितिकरण हुआ और ना ही कोई मांग पूरी हुई। पिछले 4 साल में अनियमित कर्मचारी संगठन समय-समय पर आंदोलन करता रहा है। सरकार ने हर बार कर्मचारियों को आश्वासन देकर मनाया लेकिन अब चुनाव आ गए हैं। ऐसे में अनियमित कर्मचारी संगठन एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर है। प्रदेश भर में अनियमित कर्मचारियों की संख्या 3 लाख से ऊपर है।

मोहन मरकाम को जलील करके निकाला गया : नेताम

■ **कांग्रेस अपने इतिहास की तरह ही इंडिकेट और सिंडिकेट में बंट गया है**

रायपुर। कांग्रेस अध्यक्ष पद से बुरी तरह अपमानित करके प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को निकाला जाना निंदनीय है। यह इसलिए भी और अधिक निंदनीय है क्योंकि वे कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम कर रहे थे। प्रदेश की जनता विशेषकर आदिवासी, पिछड़ों के हक का हिस्सा लूट लेने का वे विरोध करते रहे थे। दुखद यह है कि कांग्रेस की न तो भारत के संविधान में आस्था है न ही पार्टी में संविधान है। मरकाम कांग्रेस के संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए ही पार्टी चला रहे थे, उनके आदेश के विरुद्ध संविधानेत्तर आदेश निकाल देना, अन्य तरह से भी लगातार अपमानित करना, अपनी टीम तक उन्हें नहीं बनाने देना, फ़ोटो तक उनका नहीं छपने देना कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र की हत्या है। इसे सहन नहीं किया जाना चाहिये। कांग्रेस में केवल शराब घोटाले का सिंडिकेट ही नहीं है बल्कि वह अपने इतिहास की तरह ही इंडिकेट और सिंडिकेट में बंट गया है। उक्त बातें भाजपा के वरिष्ठ नेताम राम विचार नेताम ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहीं।

नेताम ने कहा कि मरकाम के अपमान से समाज में फैले आक्रोश को मैनेज करने उन्हें मंत्री पद का झुनझुना थमाने की कोशिश है। टी. एस. सिंहदेव की तरह ही इस झुनझुना का उनके लिए क्या उपयोग होगा आखिर? जो भी विभाग उन्हें दिये जायेंगे, उसे समझने में ही नये मंत्री के रूप में उन्हें काफी समय लगेगा। ऐसे में उन्हें मंत्री पद की शपथ दिला कर वास्तव में उन्हें उस भ्रष्टाचार कैबिनेट का हिस्सा बना देने की साजिश है जिस कैबिनेट के भ्रष्टाचार का वह विरोध कर रहे थे। कांग्रेस के कका पूरी तरह अब मोहन पक्ष के लिये धृतराष्ट्र बन गये हैं। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार करने के लिए जिला निर्माण समिति बना रखी है जिसके अध्यक्ष जिले के कलेक्टर होते हैं और उनके द्वारा करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार द्वारा कराए जा रहे हैं इन समितियों में बिना टेंडर के भी कार्य किए जा रहे हैं यह सरगुजा से लेकर बस्तर तक बड़ा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है ज्यादातर माइनिंग के राशि इसी माध्यम से खर्च हो रहे हैं।

अब अपराधियों की खैर नहीं, डीजीपी जुनेजा ने अधिकारियों की ली बैठक

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब अपराधिक मामलों पर लगाम लगेगा। प्रदेश में हो रहे अपराधों पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। चोर उच्चके, बदमाश, ऑनलाइन गैम्बलिंग, नशाखोरी करने वालों की अब खैर नहीं है। छत्तीसगढ़ में क्राइम पर कंट्रोल पाने के लिए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों (एसपी) और पुलिस महानिरीक्षकों (आईजी) के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली है। इस बैठक में बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं।

छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और रेंज पुलिस महानिरीक्षकों की बैठक ली। इस बैठक में सभी जिले में बीते महीनो में हुए अपराध के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षकों को ऑनलाइन गैम्बलिंग, जुआ, सट्टा, अवैध शराब और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ अधिक प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के घटनाओं में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए।

इस बैठक में चिटफंड कम्पनियों के खिलाफ कार्रवाई की समीक्षा की। पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया कि जिन प्रकरणों में विशेष न्यायालय की ओर से कुर्की, नीलामी का आदेश किया जा चुका है, उन प्रकरणों की सम्पत्तियों की नीलामी कर राशि निवेशकों को वापस दी जावे।

डीजीपी अशोक जुनेजा ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपराधियों और असामाजिक तत्वों को अपराधियों के खिलाफ ह्न्न और जिला बदर के तहत प्रभावी वैधानिक कार्रवाई करने का निर्देश दिए। फरार अपराधियों और वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने ने कहा कि सभी जिलों में की जा रही कार्रवाई की साप्ताहिक समीक्षा होगा।

संगठन में अलग-अलग लोगों को अलग-अलग जिम्मेदारी : भूपेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर सांसद दीपक बैज को पीसीसी चीफ बनाए जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि संगठन में अलग-अलग लोगों को अलग-अलग जिम्मेदारी दी जाती है। उनका दो कार्यकाल रिपीट हुआ था। सभी प्रदेशों में बदलाव किया गया है। यह निर्णय रायपुर में हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में ही लिया गया था। इसमें कहा गया था कि 50 साल से कम उम्र के लोगों को तवज्जों दिया जाए। हमारे यहां छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत भी हो गई है। सांसद दीपक बैज 42 साल के युवा हैं। 42 वर्ष के नौजवान को प्रदश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। कल उनका जन्मदिन भी है, उन्हें बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उनकी नियुक्ति से सभी कांग्रेशजनों में हर्ष का माहौल है।

बीजेपी के सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद के कांग्रेस को लेकर दिए बयान पर उन्होंने कहा कि क्या बोलना है, कब बोलना है, ये रविशंकर प्रसाद तय करेंगे क्या? रविशंकर प्रसाद अपनी चिंता करें। वह कैबिनेट से क्यों हटाए गए? इतने बड़े सीनियर मिनिस्टर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने लायर रहे हैं। उन्हें भी बीजेपी ने दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। इसके बारे में वह चर्चा करके बताएं। बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से आज रायपुर

के भारत माता चौक पर शराबबंदी को लेकर प्रदर्शन किए जाने पर सीएन ने कहा कि बिल्कुल नशाबंदी होना चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ कैबिनेट में बदलाव के सवाल पर सीएम भूपेश बघेल ने संकेत देते हुए कहा कि देखते रहिए। इंतजार कीजिए। आगे क्या होता है।

पार्टी हाईकमान के निर्देश का पालन : प्रेमसाय सिंह टेकाम

पीसीसी चीफ बदले जाने के बाद अब स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पद से हटाए जाने के बाद उन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है। कल शुक्रवार को वह मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके धनेन्द्र साहू को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आज मीडिया से चर्चा में संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि देखिए और इंतजाकर कीजिए।

विज्ञान के लोकव्यापीकरण में साईंस सेन्टर की महत्वपूर्ण भूमिका: सत्यनारायण शर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर के 12वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा ने विज्ञान लोकव्यापीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका को इंगित करते हुए इसे जन-मानस तक पहुंचाने में साइंस सेन्टर की महती भूमिका की सराहना की। उन्होंने विद्यार्थियों को विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार हेतु प्रेरित किया। इस अवसर उन्होंने रीजनल साइंस सेंटर की वेबसाइट का भी विमोचन किया गया।

मुख्य अतिथि विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा ने साइंस सेंटर के 12 वर्ष पूर्ण होने पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बच्चों में विज्ञान के प्रति हमारी रूचि कैसे बढ़े, विज्ञान विषय को रूचिकर कैसे बनाएं। इस दिशा में साइंस

सेंटर काम कर रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता के पूर्व महानिदेशक श्री जी. एस. रौतेला ने की। कार्यक्रम में विभिन्न शालाओं से आये 500 छात्र-छात्राओं ने अन्य अन्य कार्यक्रम यथा- विज्ञान प्रश्नोत्तरी, विज्ञान प्रादर्श प्रदर्शनी, वैज्ञानिक व्याख्यान एवं विज्ञान चित्र प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र तथा चयनित उत्कृष्ट विद्यार्थियों को वर्ग अनुसार पुरस्कार विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा एवं महानिदेशक श्री एस.एस. बजाज द्वारा प्रदान किया। छत्तीसगढ़ रीजनल साईंस सेन्टर का मुख्य उद्देश्य समाज के वैज्ञानिक संकाय को प्रोत्साहित करना तथा उनमें तार्किक वैज्ञानिक सोच विकसित करना है। छत्तीसगढ़ रीजनल साईंस सेन्टर अपने विभिन्न क्रियाकलापों, उपलब्ध प्रतिक्रियात्मक प्रदर्शनियों जैसे परिमापन, छत्तीसगढ़ के संसाधन एवं मनोरंजन विज्ञान गैलरियों, अस्थायी प्रदर्शनी हॉल, बच्चों का कोना, विज्ञान प्रदर्शन कोना, तारामण्डल, 3-डी रंगमंच सुविधा, विज्ञान उद्यान, वाचनालय-सह-संगोष्ठी हॉल तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाएं का उपयोग करते हुये अपने उद्देश्यों के पूर्ति के लिये स्थापना वर्ष से सतत प्रयासरत है।

ग्राम पंचायत बिर्रा व बम्हनीडीह बनेगा नगर पंचायत : मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज जांजगीर चांपा जिले के ब्रम्हनडीह विकासखंड के ग्राम बिर्रा के दशहरा मैदान में आयोजित जिला साहू संघ के शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह में शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी, भक्त माता कर्मा की पूजा-अर्चना की तथा समाज के पूर्वजों को श्रद्धासुमन अर्पित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। श्री बघेल ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए ग्राम पंचायत बिर्रा एवं बम्हनीडीह को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत बिर्रा में ही नवीन स्वामी आत्मानन्द इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने, नवीन सामुदायिक भवन बनाने, बिजली विभाग का जूनियर इंजीनियर कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की है। ग्रामीणों की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री ने हसदेव नदी पर बम्हनीडीह से दहिदा सड़क पल निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान की।

श्री बघेल ने कार्यक्रम में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। इसके लिए हमने किसानों, मजदूरों, महिलाओं, भूमिहीन मजदूरों सहित तमाम वर्गों के लिए जनहित में अनेक योजनाएं बनाई है। राज्य के 26 लाख किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। हमने धान की बम्पर पैदावार को देखते हुए इस वर्ष प्रति एकड़ 15 क्विंटल को बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी का निर्णय लिया है। हमारी सरकार शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। स्कूल जतन योजना के माध्यम से स्कूलों का रंग रोगन किया जा रहा है। इसके लिए 1000 करोड़ रूपए खर्च किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने प्रथम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श कॉलेज का किया लोकार्पण

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज कांकेर में प्रदेश के प्रथम स्वामी आत्मानंद अंगेज़ी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम से जो बच्चे हायर सेकेण्डरी स्कूलों से पढ़कर निकलेंगे, वे स्वामी आत्मानंद अंगेज़ी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों में आगे भी इसी माध्यम से पढ़ाई जारी रख सकेंगे। प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के 10 स्वामी आत्मानंद आदर्श महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। इन्हीं में से पहले स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का लोकार्पण आज कांकेर में हुआ।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि मुझे खुशी है कि आज प्रदेश के प्रथम स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का शुभारंभ कांकेर में हो रहा है। हमारा प्रयास है कि बस्तर में शिक्षा का उजियारा सभी तरफ फैले। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि रायपुर एनआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर में चयनित कांकेर की छात्राएं गरीब परिवारों की हैं। बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, आवश्यकता उन्हें अवसर

प्रदान करने की है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कांकेर जिले में आयोजित इस कार्यक्रम में कांकेर जिले में स्कूली बच्चों के लिए संचालित हमर लक्ष्य कार्यक्रम अंतर्गत एनआईटी रायपुर में चयनित तीन छात्राओं तथा सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर में चयनित एक छात्रा से बातचीत की और उन्हें सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। गरीब परिवारों की इन छात्राओं को राज्य शासन द्वारा आगे की पढ़ाई के लिए सहायता राशि प्रदान की जा रही है। हमर लक्ष्य कार्यक्रम के तहत कांकेर जिले के 75 बच्चों ने जेईई में क्वालीफाई किया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कांकेर जिले में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों जिन्हें नौकरी मिली है, उनके साथ तथा कांकेर के अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय के छात्रों से संवाद किया। वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान कांकेर में संसदीय सचिव एवं विधायक कांकेर श्री शिशुपाल सोरी, विधायक अंतागढ़ श्री अनूप नाग, विधायक भानुप्रतापपुर श्रीमती सावित्री मंडावी, अध्यक्ष नगर पालिका श्रीमती सरोज ठाकुर, कलेक्टर डॉ प्रियंका शुक्ला, पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवार के विद्यार्थी को भी अंग्रेजी माध्यम में उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिए वर्ष 2020 में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय की शुरुआत की गई। यह योजना प्रदेश में काफी लोकप्रिय हुई। भेंट मुलाकात के दौरान प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्वामी आत्मानंद विद्यालयों की मांग की जाती थी, जिसके आधार पर अनेक स्कूलों की शुरूआत हुई। प्रदेश में आज स्वामी आत्मानन्द योजना के अंतर्गत अंग्रेजी माध्यम के 377 और हिंदी माध्यम के 350 स्कूल संचालित हो रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत अब तक तीन किश्तों में 01 लाख 17 हजार हितग्राहियों को 80 करोड़ रूपए की राशि दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में पिछले साढ़े चार सालों में 26 हजार 989 शिक्षकों की भर्तियां निकाली गई हैं। पहले 14 हजार 500 शिक्षकों की भर्तियां निकाली गई थी, इनमें से 10 हजार 834 शिक्षकों को स्कूलों में नियुक्तियां दी जा चुकी है। हाल ही में 12 हजार 489 शिक्षकों की और भर्तियां निकाली है, जोकि प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग के सभी जिलों में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में प्राथमिकता के साथ काम किया गया है। बस्तर संभाग के 314 बंद स्कूलों को पुनः खोला गया। बेरोजगार युवाओं को नियमित रूप से बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों से बस्तर में विश्वास, विकास और सुरक्षा का वातावरण बना है। संसदीय सचिव श्री शिशुपाल सोरी ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना से बच्चे उत्साहित हैं। बस्तर अंचल के बच्चे भी स्मार्ट हों और उन्हें बड़े पदों पर सेवा का अवसर मिले।

सरकार बनी तो नियमित कर सकती है भाजपा

घोषणापत्र में शामिल करेंगे ये मुद्दा; संविदा प्रथा का फूंका गया पुतला

■ तूता स्थित धरना स्थल में प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को रमन सिंह ने किया संबोधित

रायपुर। नवा रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल में प्रदेश के संविदा कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। गुरुवार को यहां प्रदेश के पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह पहुंचे। कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन करते हुए डॉ रमन सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में भाजपा नियमितीकरण को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्हें भाजपा की सरकार बनने पर नियमित करने का इशारा भी किया। इसके साथ ही अगले चुनाव में उन्होंने कर्मचारियों से अपील की है कि, अगले चुनाव में बीजेपी का साथ दें।

गुरुवार को तूता के धरना स्थल में संविदा कर्मचारी, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई, रसोइया संघ और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ के लोगों ने आंदोलन किया। जिसमें बीजेपी नेता ओपी चौधरी, गौरी शंकर श्रीवास पहुंचे। डॉ रमन सिंह ने यहां कहा, भाजपा ने हमेशा 1988 में और 1997 में कर्मचारियों को रेगुलर किया। 40 हजार से अधिक नियमितिकरण भाजपा ने किए हैं। जबकि कांग्रेस पिछले पौने 5 वर्षों से केवल झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं कर पाई है।

संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रांताध्यक्ष कौशलेश तिवारी ने कहा, लोकतंत्र में सम्मानपूर्वक काम और संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। लेकिन जब शासन की योजनाओं को धरातल पर लागू करने वाले कर्मचारियों को हर साल नौकरी से निकाले जाने का भय और कार्य के दौरान प्रशासनिक प्रताड़ना का प्रति दिन सामना करना पड़ता हो तो उनकी स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

कर्मचारी नेताओं ने कहा, छत्तीसगढ़ में सरकारें तो बदली पर हमारे भाग्य नहीं बदले। हम आज भी अपने सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सिन्हा का कहना है कि इतिहास में यह काला दिन होगा। हमने सुना था कि सरकार संवेदनशील होती है। लेकिन स्थिति बिल्कुल विपरीत है। संविदा कर्मचारियों के प्रति कोई संवेदना नहीं है। हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है।

महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक कुर्रे ने कहा कि, स्वास्थ कर्मचारियों पर लगाया गया एस्मा कानून तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में यह वादा किया गया था, कि संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण किया जाएगा। इसी वादे को पूरा करने की हम अपील कर रहे हैं।

अमृत सरोवर योजना के तहत नए तालाबों का करें निर्माणः सांसद सोनी

रायपुर। सांसद सुनील सोनी के अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक हुई। बैठक में पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री पंकल शर्मा, रायपुर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, नगर निगम आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अबिनाश मिश्रा, सहायक कलेक्टर श्री जयंत नहाटा उपस्थित थे।

बैठक में सांसद श्री सोनी ने संबोधित करते हुए कहा कि अमृत सरोवर योजना के तहत अमृत काल में आने वाली पीढ़ियों के लिए नई जल संरचना विकसित करना है। इस अवधि में जिले के विभिन्न भागों में नए वाटर बाडी जैसे नए तालाबों का निर्माण किया जाए और पुराने तालाबों को भी संरक्षित किया जाए। उन्होंने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत् कौशल उन्नयन के कार्य किए जाए और आजीविका के अवसरों में बढोत्तरी कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम किया जाए। साथ ही वन डिस्ट्रीक वन ब्रान्ड के तर्ज पर क्षेत्रवार कौशल-कला का विकास करें। श्री सोनी ने जिले के सभी अधिकारियों को योजनाओं के तहत मंजूर किए गए कामों की सतत मॉनिटरिंग-समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजनों की सहुलियत के लिए स्वीकृत किए गए विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए लगातार समीक्षा की जानी चाहिए।

जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा ने कहा कि जुलाई से सामाजिक पेंशन योजना में राज्य सरकार द्वारा राज्यांश में वृद्धि की गई है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा कौशल उन्नयन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे है। इसका आम लोगों को लाभ दिलाएं। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री शर्मा ने योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सुझाव दिए। श्री सोनी ने कहा की प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत बने सड़कों का बरसात के पश्चात निरीक्षण कर मरम्मत कराएं। प्रधानमत्री आवास योजना के तहत केन्द्र और राज्य सरकार का अंशदान मिल चुका है। इसलिए हितग्राहियों को अधिक से अधिक लाभ दिलाएं। जिन हितग्राहियों को प्रथम किस्त दी गई है और उन्हें जल्द दूसरी किस्त दिला कर आवास को पूर्ण कराएं। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना प्रारंभ कर चुकी है अत: इसके तहत सर्वे कराकर हितग्राहियों को लाभ दिलाया जा सकता है। श्री सोनी ने इस योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले अवांछित तत्वों का कार्रवाई करने का निर्देश दिए।

शराबबंदी बयान को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने मंत्री अकबर के निवास का घेराव किया

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने गुरुवार को शराबबंदी को लेकर दिए गए एक बयान के मद्देनजर प्रदेश सरकार के मंत्री मो. अकबर के खिलाफ भारत माता चौक पर आंदोलन कर रैली निकाली और उनके निवास का घेराव किया। आंदोलन व रैली का नेतृत्व महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने किया। भाजपा महिला मोर्चा ने मंत्री अकबर के उस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है, जिसमें मंत्री अकबर ने कहा था कि 'हमने शराबबंदी के लिए गंगाजल की कसम नहीं खाई है, हमने कर्जा माफी के लिए गंगाजल की कसम खाई थी।' मंत्री अकबर के बयान को पूरे प्रदेश की महिलाओं का घोर अपमान बताते हुए महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती राजपूत ने मंत्री अकबर से अपने इस कथन के लिए मातृ-शक्ति से बिना शर्त क्षमायाचना करने की मांग की है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने मंत्री अकबर के इस कथन को सफेद झूठ और अपने वादे से निर्लज्जतापूर्वक मुकरना बताया। श्रीमती राजपूत ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्ण शराबबंदी का वादा गंगाजल की सौगंध लेकर कांग्रेस के तमाम नेता हर चुनावी मंच पर कर रहे थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस वादाखिलाफी पर उतर आई।

पूरे प्रदेश की जनता जानती है गंगाजल को साक्षी मानकर पूरे प्रदेश में शराब पर प्रतिबंध और पूर्ण शराबबंदी का वादा चुनावी मंचों से चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने किया था। माताओं बहनों को शराबबंदी का झाँसा देकर उनका वोट बटोरा गया और अंत में उन्हें ठग दिया गया। श्रीमती राजपूत ने कहा कि शराब घोटाले में आकंठ डूबी हुई यह सरकार भयभीत है कि कहीं शराबबंदी कर दी गई तो शराब ठेकेदार इनके भ्रष्टाचार को सार्वजनिक कर देंगे। 2000 करोड़ के शराब घोटाले पर इनके सचिव और करीबी पहले से ही जेल में हैं और प्रदेश सरकार के मंत्री अब शर्मनाक तरीके से कहते हैं कि प्रदेश में शराबबंदी की हमने कोई कसम नहीं खाई थी। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती राजपूत ने कहा कि प्रदेश सरकार और उसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराबबंदी के नाम पर तमाम तरह की ड्रामेबाजी करने में पूरा कार्यकाल बिता दिया।

शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा फैसला हाईकोर्ट ने रोक हटाई

बिलासपुर। प्रदेश में 14 हजार शिक्षकों व लेक्चरर की भर्ती प्रक्रिया को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व में जारी रोक को हटा लिया है। साथ ही राज्य शासन को आगे की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की छूट दी है। कोर्ट ने पांच याचिकाकर्ताओं के लिए पांच पद आरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि वेद प्रकाश एवं अन्य ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षक के टी संवर्ग के चार हजार 659 पद पर एवं ई संवर्ग के एक हजार 113 पदों की भर्ती हेतु चार मई 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमें शिक्षक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का प्रावधान किया गया है, जबकि नियमों में इस संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि विज्ञापन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस विषय के शिक्षक के लिए कितने पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को इस बात की जानकारी आखिर तक नहीं मिल पाएगी कि जिस विषय के शिक्षक पद के लिए उसने आवेदन जमा किया है और परीक्षा दी है, उसमें कितने पद है। पदोन्नति एवं सेवा भर्ती नियम के विपरीत विज्ञापन जारी किया गया है। अंग्रेजी, गणित, संस्कृत आदि विषयों के लिए अलग-अलग पद जारी किया जाना था। शासन की ओर से महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा व उपमहाधिवक्ता संदीप दुबे ने पैरवी की। कोर्ट को बताया गया कि नियमों में संशोधन कर दिया गया है। सहायक शिक्षक व शिक्षकों के लिए नियम बना दिया गया है।

उप स्वास्थ्य और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण का फैसला

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की राज्य स्तरीय समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्पन्न हुई। बैठक में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के भवन विहीन उप स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन बनाने एवं शहरी क्षेत्रों के हेल्थ एण्ड वेलनेस केन्द्र एवं पाली क्लिनिक के संचालन के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न अस्पतालों के लिए दवाईयां, उपकरणों इत्यादि क्रय किए जाने प्रस्तावित किया गया। बैठक में अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती रेणु जी पिल्ले भी मौजूद थी। बैठक में राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु स्वास्थ्य केन्द्र जिनके भवन नहीं है उनके भवन बनाना प्रस्तावित किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक में इलाज वाले समस्त मरीजों का ऑनलाइन डाटा प्रविष्ट किए जाने हेतु आईटी सिस्टम को सुदृढ़ किए जाने और भारत नेट के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा सुनिश्चित करने तथा भविष्य में मरीजों का ऑनलाइन डाटा संधारित करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसी प्रकार से प्रदेश के 544 भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्र और 20 भवन विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु अधोसंरचना निर्माण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। इसी तरह से प्रदेश के सभी उप स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपकरणों संबंधी सेवाएं प्रदान करने का कार्य सीजीएमएससी से कराया जाना प्रस्तावित किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित इस बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रसन्ना आर., नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव अयाज तम्बोली, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोसकर विलास संदिपान सहित राज्य स्तरीय समिति के अन्य सदस्य शामिल हुए।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

दीपक बैज का किया जायसवाल ने स्वागत

रायपुर। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी नाथ जायसवाल ने आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष युवा सांसद दीपक बैज को काशी विश्वनाथ जी का अंग वस्त्र व रुद्राक्ष की

माला के साथ काशी विश्वनाथ जी का प्रसाद खिलाकर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के माटी के लाल को तहेदिल से बधाइयां दीं। आगे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी नाथ जायसवाल ने कहा कि युवा प्रदेश अध्यक्ष मिलने से छत्तीसगढ़ प्रदेश के संगठन को और भी मजबूती मिलेगी। अपने नवाचार योजनाओं से दीपक बैज ने बस्तर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ को प्रभावित किया है और निश्चित रूप से इस बार 75 पार के आंकड़े को हम छूने जा रहे हैं नवनिर्वाचित माननीय सांसद दीपक बैज जी के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस फेडरेशन के सदस्यों ने हमेशा कांग्रेस पार्टी का सहयोग निस्वार्थ भाव से किया है। और निश्चित रूप से इस बार 75 पर के आंकड़े को छूने में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस मिल का पत्थर साबित होगा। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विश्वास दिलाता हूं कि हमारे संगठन के प्रत्येक सदस्य जहां भी जरूरत पड़े, जैसे भी जरूरत पड़े हर किसी स्थिति- परिस्थिति में साथ रहेगा।

कांग्रेस का घमासान सत्ता परिवर्तन का संकेत : चंदेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार का अंतर्विरोध और भारी गुटबाजी सड़कों पर देखने को मिल रही है, यह अंतर्विरोध की चरम सीमा है। प्रेमसाय सिंह

टेकाम का यह बयान कि 'इस्तीफा दिया नहीं जाता ले लिया जाता है' स्वयं कहता ही कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार के मंत्रियों से इस्तीफा लिया जा रहा है। उन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। यह इस बात का संकेत है कि कि कांग्रेस इस प्रदेश में किन हालातों से गुजर रही है। कांग्रेस में स्वेच्छाचारिता, हिटलरशाही और एकला चलो की नीति की यह परिणति देखकर हमें लग रहा है कि सत्ताधारी दल में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, यह परिवर्तन छत्तीसगढ़ विधानसभा के आने वाले चुनाव में सत्ता के परिवर्तन का संकेत है। अब कांग्रेस की विदाई तय है और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी सुनिश्चित है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि कल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम हिटलरशाही के शिकार हो गए। आज अचानक मंत्रियों से इस्तीफे मांगे गए। कांग्रेस और उसकी सरकार में यह क्या उठापटक चल रही है। न संगठन अध्यक्ष पर भरोसा, न भूपेश बघेल सरकार के मंत्रियों पर भरोसा। यदि भूपेश बघेल के मंत्री निकम्मे हैं तो पौने पांच साल से उन्हें क्या सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए रखा गया था। मंत्रियों के कार्य प्रदर्शन की जिम्मेदारी उनका नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री की है।

चौतरफा निराशा में डूबी भाजपाः कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा नेताओं के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि चौतरफा निराशा में डूबी भाजपा डिप्रेशन का शिकार है। इसके केंद्रीय नेताओं से लेकर स्थानीय नेताओं तक का

मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हिमाचल, कर्नाटक के बाद अब पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में बुरी तरह ठुकराए जाने से भाजपा को अहसास हो गया है कि अब पूरे देश में दुर्गति होना तय है। छत्तीसगढ़ में तो भाजपा की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि पार्टी का अस्तित्व बचाने छत्तीसगढ़ दौरे के लिए मोदी - शाह दौड़ लगा रहे हैं। तू चल, मैं आया की तर्ज पर एक आकर जाता है तो दूसरा चला आता है। चार साल से छत्तीसगढ़ को भूले बैठे मोदी को अब हर हफ्ते छत्तीसगढ़ का सपना आ रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी के जयकारे लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाजपा में महाभारत इस तरह चरम पर है कि केंद्रीय गृह मंत्री देश की चिंता छोड़ छत्तीसगढ़ भाजपा की वजूद बचाने बार -बार आ रहे हैं और हर बार निराश होकर जा रहे हैं। सब कुछ बदल के देख लिया। लेकिन भाजपा की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा। मोदी- शाह वेंटिलेटर बन कर कृत्रिम सांसें दे रहे। कोई फर्क नहीं पड़ना। छत्तीसगढ़ भाजपा के सारे नेताओं की बयानबाजी साबित कर रही है।

स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम स्कूलों में 9117 पदों पर होगी भर्ती

रायपुर। स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम के 318 स्कूलों में 9117 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसको लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आत्मानंद स्कूलों में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए नियमावली जारी कर दी गई है। सभी पद स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही भरे जाएंगे। प्रत्येक स्कूल हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में एक सोसायटी का गठन किया गया है। इन स्कूल के संचालन हेतु गठित सोसायटी को भर्ती एवं स्कूल संचालन के अधिकार हस्तांतरित किए गए हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी स्कूलों में प्राचार्य, उप प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठक (प्राइमरी एवं मीडिल स्कूल), शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, कम्प्यूटर शिक्षक, सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला), ग्रंथपाल, लेखापाल एवं सहायक ग्रेड-02, सहायक ग्रेड-03, भृत्य, चौकीदार एवं अंशकालीन सफाई कर्मी के पद पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए राज्य शासन द्वारा सोसायटी को पद अंतरित कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश में शिक्षा सत्र 2022-23 से 32 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालयों का संचालन कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति को सौंपा गया था।स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल संचालन के संबंध में सोसायटी की नियमावली तय की गई है, जिसके अनुसार विद्यालय के संचालन के लिए पंजीकृत सोसायटी के राज्य शासन द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा और सोसायटी अन्य स्त्रोतों से भी धन जुटा सकेगी।

भाजपा नेत्रियां शराबबंदी को लेकर कर रही नौटंकी : वंदना

रायपुर। भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा शराबबंदी को लेकर किये जा रहे आंदोलन को नौटंकी मात्र है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने भाजपा महिला मोर्चा आंदोलन पर कटाक्ष करते हुये कहा कि भाजपा नेत्रियां गिरगिट

की तरह रंग बदलती है। 15 साल भाजपा के शासन में रमन सिंह सारे नियम को ताक में रखकर आबकारी नीति को परिवर्तित कर दिया जाता है। युवाओं के हाथ में पुस्तक के बदले शराब का बोतल पकड़ा दिया है। तब भाजपा नेत्रियों की मुंह में दही जम गया था। भाजपा नेत्री 15 साल तक मूकदर्शक बनी मलाई खाते है। जब सत्ता हाथ से फिसल जाती है तब भाजपा नेत्रियों को अहसास होता है कि शराबबंदी होना चाहिए।प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा नेत्रियों को शराब को लेकर नौटंकी करने की जरूरत नहीं है उनकी वास्तविक चेहरा उजागर हो गई है। जनता के सामने में रमन सिंह सरकार में रहते शराब का सरकारीकरण करने के बजाय शराबबंदी क्यों नहीं किये? रमन सिंह ने सार्वजनिक घोषणा किया था चुनाव हार जाऊं तो कोई बात नहीं शराबबंदी लागू करूंगा। फिर शराब का सरकारीकरण क्यों किया? 4400 करोड़ का शराब घोटाला होता है। भाजपा सत्ता में काबिज होने के लिए जनता को गुमराह करती है चाहे मोदी जी की 2014 की वादे की बात करें।

बिक जाएंगी 17 सिटी बसें, साधारण सभा में हुआ निर्णय

रायपुर। रायपुर जिला शहरी सार्वजनिक सर्विस सोसाईटी की साधारण सभा की बैठक कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट परिसर स्थित कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में रायपुर जिला शहरी सार्वजनिक सर्विस सोसाईटी के द्वारा संचालित सिटी बसों के संबंध में चर्चा हुई। बैठक मे बताया गया कि वाहन कम्पनी द्वारा अधिकृत डीलर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कुल 17 सिटी बसों के स्पेयर्स पार्ट्स आसानी से उपलब्ध न होने से मरम्मत नही होने की जानकारी दी गई है। साथ ही यह भी बताया

गया है कि स्पेयर्स पार्ट्स उपलब्ध होने पर भी प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय आएगा। अतएव समस्त 17 बसों को सिटी बसों के रूप मे चिन्हित मार्ग में संचालन हेतु नही माना गया है।

बैठक में जानकारी दी गई कि वाहन की वर्तमान औसत आयु 07 वर्ष की हो चुकी है जबकि शासन के नियमानुसार डीजल चलित वाहन को 15 वर्ष तक संचालित किए जाने का प्रावधान है। अत: उक्त बसों को स्क्रैप न करते हुए मूल्यांकन कराने के पश्चात् बेचने का निर्णय लिया गया।

बैठक में युवतियों के कौशल उन्नयन के लिए नवगुरूकुल फाउंडेशन पर चर्चा हुई। जिसके अनुसार यह निर्णय लिया गया कि बेरोजगारी भत्ते से ही चिन्हित छात्राओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। छात्राओं को रूकने तथा प्रशिक्षण हेतु चिन्हित भवनों या हॉस्टल में किए जाने सोसायटी मद से किए जाने की स्वीकृति दी गई। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी, आरटीओं श्री शैलाभ साहु, सीएमएचओं श्री मिथलेश चौधरी सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।

भाजयुमो का दल मिला जोन आयुक्त से, सौंपा ज्ञापन

रायपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा का दल हांडी तालाब पर पचरी निर्माण के नाम पर 12 से 15 फिट के गड्ढे करके यथावत छोड़ दिया गया यह स्थान बहुत ही सघन बस्ती और भीड़ भरा इलाका है जो अमापारा शीतला मंदिर के पीछे तत्यापारा वार्ड क्षेत्र में आता है। स्थानीय पार्षद से शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही ऐसे में स्थानीय नागरिकों ने भाजयुमो नेताओ से संपर्क साधा भाजयुमो जिला महामंत्री राहुल राव के नेतृत्व में अन्य कार्यकर्ता स्थानीय नागरिकों सहित जोन क्रमांक 7 में आयुक्त से मुलाकात की।

भाठागांव - रिंग रोड शराब दुकान बंद कराने कन्हैया अग्रवाल के नेतृत्व में सत्याग्रह

रायपुर। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के पास भाठागांव रिंग रोड में स्थित शराब दुकान के कारण आसपास क्षेत्र की बस्तियों और कॉलोनियों में रहने वाले नागरिक परेशान हैं । उनकी परेशानी को दूर करने शराब दुकान बंद करने की मांग को लेकर सत्यमेव जयते फउंडेशन के प्रदेश संयोजक कन्हैया अग्रवाल के नेतृत्व में एक दिवसीय उपवास / सत्याग्रह किया गया। सत्यमेव जयते फउंडेशन के सुरेश बाफ्ना और मुकुंद कागदेलवार ने उक्ताशय की जानकारी देते हुए बताया कि कि क्षेत्र में होने वाली परेशानी को दूर

करने आवश्यक कार्रवाई के लिए दो माह पूर्व जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था उन्होंने आश्वस्त किया था की आबकारी विभाग को निर्देशित करेंगे ,जिला आबकारी अधिकारी ने कहा था शराब दुकान स्थानांतरण के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा, पर दो महीने बाद भी शराब दुकान बंद नहीं होने के कारण एक दिवसीय सत्याग्रह किया गया । उल्लेखनीय है कि रिंग रोड में स्थित शराब दुकान के कारण सोनकर पारा, क्रुस्क, आनंद नगर, ब्रह्मदेव कॉलोनी , वालफोर्ट सिटी ,दंतेश्वरी मंदिर, छर्रीपारा, उत्तम नगर,आस्क सिटी सहित आसपास की महिलाएं नशेडियों के कारण उस मार्ग से गुजरने में से डरती हैं । पूरी सड़क में नशा करने वालों की वजह से वातावरण खराब रहता है ।कॉलोनी और बस्तियों के नागरिक शराब दुकान से होने वाले परेशानी को लेकर उद्वेलित हैं ।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.